Website : www.mantrabharat.com

जुनून है सच लिखने का

E-Mail : mantrabharatmumbai@gmail.com, Mo. 7007837917

संस्करण : मुंबई
वर्ष : 11
अंक : 16
पृष्ठ : 8
मूल्य : 2.00
शुक्रवार, 23 जनवरी, 2026

मंत्र भारत

हिन्दी दैनिक

मुंबई, लखनऊ, प्रयागराज एवं ग्वालियर से एक साथ प्रकाशित एवं ठाणे, नवी मुम्बई, पालघर, नासिक एवं पुणे से प्रसारित

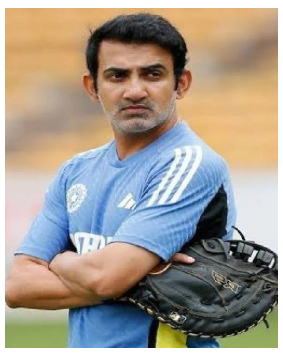

3 लंबित मामलों के निपटारे से त्वरित न्याय प्राप्त ... 4 एआई सुपरपावर बनने का सपना, मगर शिक्षा... 7 तब 'असीमित अधिकार' को लेकर सच्चाई ...

दावोस में महाराष्ट्र के 30 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौते : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

अतिरिक्त 10 लाख करोड़ रुपये के समझौतों पर प्रारंभिक वार्ता पूर्ण

दावोस। दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान महाराष्ट्र ने 30 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौते किए हैं तथा अतिरिक्त 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौतों पर प्रारंभिक वार्ता पूरी हो चुकी है। इन निवेशों के माध्यम से राज्य में 40 लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य है, यह जानकारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज दी। महाराष्ट्र के पत्रकारों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि इन समझौतों में से 83 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के हैं। कुल 18 देशों से महाराष्ट्र में निवेश आ रहा है, जबकि 16 प्रतिशत निवेश विदेशी तकनीकी भागीदारी के माध्यम से होगा।

इन देशों में अमेरिका, इंग्लैंड, सिंगापुर, जापान, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड, नॉर्वे, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, यूएई, स्पेन, कनाडा, बेल्जियम आदि शामिल हैं।

औद्योगिक, सेवा, कृषि और प्रौद्योगिकी सहित सभी क्षेत्रों में यह निवेश आ रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समझौता ज्ञापनों के वास्तविक रूप से क्रियान्वित होने की दर 75 प्रतिशत है तथा पिछले वर्ष किए गए 75 प्रतिशत समझौते धरातल पर उतर चुके हैं।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि यह निवेश अगले 3 से 7 वर्षों में चरणबद्ध रूप से मूर्त रूप लेगा। एसबीजी, ब्रुकफील्ड, आर्सेलर मित्तल, फिनमैन ग्लोबल, इस्सार, स्कोडा ऑटो, फॉक्सवैगन, एसटीटी टेलिमीडिया, टाटा, अदानी, रिलायंस, जेबीएल, कोका-कोला, बॉश, कैपिटलैंड, आयरन माउंटेन जैसी अनेक कंपनियों के साथ समझौते किए गए हैं। कुछ समूह भारतीय हैं, लेकिन उनकी गतिविधियां 165 से अधिक देशों में फैली हुई हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (उण्), डेटा सेंटर्स, स्वास्थ्य, खाद्य प्रसंस्करण, ग्रीन स्टील, शहरी विकास, जहाज निर्माण, फिनटेक, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में यह निवेश प्राप्त हुआ है।

राज्यभर में निवेश

कुल निवेश में से 22 प्रतिशत कोकण और एमएमआर क्षेत्र में, 13 प्रतिशत विदर्भ में और 50 प्रतिशत राज्य के अन्य भागों में किया जाएगा।

उत्तर महाराष्ट्र (नाशिक, जलगांव, धुले, अहिल्यानगर) में 50 हजार करोड़ रुपये, मराठवाड़ा (छत्रपति संभाजीनगर) में 55 हजार करोड़ रुपये, कोकण क्षेत्र में 3.5 लाख करोड़ रुपये तथा नागपुर व विदर्भ में 2.70 लाख करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, जायका, जेबीआईसी, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टैनफोर्ड बायोडिज़ाइन जैसे संस्थानों के साथ भी समझौते किए गए हैं।

देश की पहली 'इनोवेशन सिटी'

मुख्यमंत्री ने बताया कि टाटा समूह के सहयोग से मुंबई के पास देश की पहली इनोवेशन सिटी विकसित की जाएगी। अगले 6 से 8 महीनों में इसका विस्तृत नियोजन तैयार किया जाएगा। इस परियोजना में टाटा समूह द्वारा 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जाएगा, जबकि अन्य अंतरराष्ट्रीय निवेशक भी इसमें भागीदारी करेंगे।

मुंबई में सर्कुलर इकोनॉमी का विकास

मुंबई में सर्कुलर इकोनॉमी विकसित की जाएगी, जिससे पानी, हवा और कचरा प्रबंधन से जुड़े मुद्दों का समाधान किया जाएगा। सभी प्रकार के अपशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण किया जाएगा। अगले 2 से 3 वर्षों में इसके ठोस परिणाम दिखाई देंगे और बाद में इस मॉडल को अन्य बड़े शहरों में भी लागू किया जाएगा।

दावोस में रायगढ़-पेण ग्रोथ सेंटर की भी घोषणा की गई, जिससे एक नया बिजनेस डिस्ट्रिक्ट विकसित होगा। इस केंद्र के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश पहले ही प्राप्त हो चुका है।

अन्य महत्वपूर्ण बैठकें

जिम्बाब्वे के विदेश और अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री प्रो. एमोन मुरविरा ने एक सम्मेलन में महाराष्ट्र की सौर ऊर्जा क्षेत्र में प्रगति की सराहना की।

मुख्यमंत्री को पता है कोई भी कलेक्टर बिना पैसे काम नहीं करते सीएस के बयान पर गरमाई सियासत

भोपाल **(एजेंसी)**। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन के कथित वक्तव्य ने राज्य के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को सरकार पर हमला बोलने का अवसर दे दिया है। कांग्रेस मुख्य सचिव अनुराग जैन के उस बयान पर हमलावर हो गई है जिसमें उन्होंने कल कलेक्टर-कमिश्नर कांफ्रेंस में जिले के कलेक्टर्स को कथित तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि कोई ये नहीं समझे कि कुछ छिपा हुआ है। जिलों में क्या हो रहा है, उन्हें सब पता है। जिलों की शिकायतें उनके और मुख्यमंत्री के पास तक पहुंच रही हैं, समय रहते सुधर जाएं। मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री के हवाले से कहा कि कोई भी कलेक्टर बिना पैसे लिए काम नहीं करता। इस कथित वक्तव्य को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का संदर्भ देते हुए कहा, "जब आपको यह सब मालूम है, तो अब तक एक भी कलेक्टर पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? या फिर भाजपा सरकार में मंत्री और भाजपा विधायक भी इस भ्रष्ट तंत्र के हिस्सेदार हैं, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही? मध्य प्रदेश को 20 साल से भाजपा ने भ्रष्टाचार की राजधानी बना दिया है, जहां एक भी फाइल बिना 'चाय पानी' के पास नहीं होती।"

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया पर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, "मुख्य सचिव स्वयं कह रहे हैं कि 'मुख्यमंत्री जी का कहना है बिना पैसे लिए कोई कलेक्टर काम नहीं करता' यह बयान भाजपा सरकार में फैले भ्रष्टाचार की पोल खोलती सच्चाई है! मुख्यमंत्री जी, यह विपक्ष का आरोप नहीं, आपकी ही व्यवस्था की स्वीकारोक्ति है। जब जिले चलाने वाले जिम्मेदार अफसर ही लेन-देन की स्वार्थी प्रक्रिया में जकड़े हों, तो आम जनता को न्याय, सेवा और पारदर्शिता कैसे मिलेगी? यह सुशासन नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार का संस्थागत मॉडल है।" उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता मांग कर रही है कि मध्यप्रदेश को दलालों और कमीशनखोरी से मुक्त किया जाए।

झारखंड के चाईबासा मुठभेड़ में 15 नक्सली ढेर 1 करोड़ का इनामी 'अनल दा' भी मारा गया

रांची। झारखंड के चाईबासा जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े अभियानों में से एक को अंजाम दिया है। झारखंड पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की संयुक्त कार्रवाई में 15 नक्सली मारे गए हैं। इस मुठभेड़ की सबसे बड़ी सफलता 1 करोड़ रुपये के इनामी नक्सली अनल दा का खात्मा है। यह मुठभेड़ चाईबासा के घने जंगल इलाके में हुई, जब सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी के आधार पर तलाशी अभियान शुरू किया। ऑपरेशन के दौरान, नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब

में सुरक्षा बलों ने भी भारी जवाबी फायरिंग की। अधिकारियों के अनुसार, गोलीबारी में 15 नक्सली मारे गए। बड़ी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद भी बरामद होने की आशंका है। इलाके में अभी भी तलाशी अभियान जारी है और सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया है ताकि कोई भी नक्सली भाग न सके। अधिकारियों के मुताबिक, मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। सुरक्षा बलों को अंदेशा है कि कुछ और नक्सली घायल अवस्था में जंगल के भीतर छिपे हो सकते हैं। चाईबासा के इन घने जंगलों में अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि किसी भी नक्सली को भागने का मौका न मिले। झारखंड में नक्सलवाद की कमर तोड़ने की दिशा में इसे एक ऐतिहासिक सफलता माना जा रहा है। अनल दा जैसे बड़े कमांडर का मारा जाना नक्सली संगठन के लिए एक अपूरणीय क्षति है।

झारखंड में एक करोड़ का इनामी अनल समेत 16 ढेर, अमित शाह बोले- नक्सलवाद अब अंतिम चरण में

नई दिल्ली। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और झारखंड पुलिस द्वारा चलाए जा रहे एक संयुक्त ऑपरेशन में कुख्यात नक्सली नेता अनल उर्फ पतिराम मांझी समेत कुल 16 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। मारे गए नक्सलियों में अनल उर्फ पतिराम मांझी नक्सली संगठन का सेंट्रल कमेटी मेंबर था और उस पर 1 करोड़ रुपये का इनाम घोषित था। वह लंबे समय से नक्सली हिंसा और आतंकी

गतिविधियों में शामिल रहा था।

गृह मंत्री ने इसे बताई बड़ी उपलब्धि

सुरक्षा बलों की तरफ से की गई इस कार्रवाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी उपलब्धि बताई। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई नक्सलमुक्त भारत अभियान की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। दशकों से देश के कई हिस्सों में भय और हिंसा फैलाने वाला नक्सलवाद अब अंतिम दौर में है।

31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद खत्म करने का संकल्प

इस दौरान गृह मंत्री ने दोहराया कि सरकार का लक्ष्य 31 मार्च 2026 से पहले देश से नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करना है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल लगातार साहस और रणनीति के साथ अभियान चला रहे हैं। इसके साथ ही अमित शाह ने शेष नक्सलियों से अपील की कि वे हिंसा, आतंक और हथियारों का रास्ता छोड़कर विकास और विश्वास की मुख्यधारा से जुड़ें। उन्होंने कहा कि सरकार आत्मसमर्पण करने वालों के पुनर्वास और बेहतर भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है।

गणतंत्र दिवस से पहले आतंक पर करारा प्रहार, जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों ने चलाया निर्णायक अभियान

श्रीनगर **(एजेंसी)**। गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू कश्मीर एक बार फिर आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक मोर्चे पर खड़ा दिखाई दे रहा है। सुरक्षा बलों ने साफ संकेत दे दिए हैं कि इस बार किसी भी साजिश को पनपने का अवसर नहीं दिया जाएगा। जम्मू शहर से लेकर किश्तवाड़ और शोपियां तक चल रहे सघन तलाशी अभियानों ने आतंकियों की कमर तोड़ दी है और उनके मददगार तंत्र में खलबली मचा दी है। हम आपको बता दें कि जम्मू के बाहरी इलाकों- भाटिंडी नारवाल और राजीव नगर में पुलिस और केंद्रीय बलों ने घर घर तलाशी अभियान चलाया। गणतंत्र दिवस को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए यह कार्रवाई बेहद सख्त और सुनियोजित रही। सीमा क्षेत्रों और राजमार्गों पर निगरानी बढ़ाई गई है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को समय रहते रोका जा सके। सुरक्षा एजेंसियां साफ कर चुकी हैं कि राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए अब कोई नरमी नहीं है। किश्तवाड़ जिले के ऊंचाई वाले जंगलों में हालात और भी गंभीर रहे। चतरू

क्षेत्र के सोनार और मंद्रल सिंहपोरा में आतंकियों की मौजूदगी की पुख्ता सूचना के बाद सेना ने अतिरिक्त जवान तैनात किए। ऑपरेशन त्राशी एक के तहत चल रहे इस अभियान में जवानों ने दुर्गम इलाकों में भी मोर्चा संभाले रखा। रविवार से शुरू हुई मुठभेड़ में एक वीर पैराट्रूपर शहीद हुआ और कई जवान घायल हुए लेकिन अभियान रुका नहीं। आतंकियों द्वारा छिपकर किए गए ग्रेनेड हमले और लगातार गोलीबारी के बावजूद सुरक्षा बलों ने दबाव बनाए रखा।

मुठभेड़ स्थल के पास एक बड़ा आतंकी ठिकाना उजागर होना इस बात का प्रमाण है कि आतंकी संगठन गहरी साजिश के साथ इलाके में जड़ें जमाने की कोशिश कर रहे थे। खुफिया एजेंसियों का अनुमान है कि इस क्षेत्र में दो से तीन आतंकी सक्रिय हैं जिनका संबंध सीमा पार बैठे आतंकी आकाओं से है। आज वहां फिर से गोलीबारी शुरू होना बताता है कि आतंकी घिर चुके हैं और बौखलाहट में हैं। हम आपको यह भी बता दें कि दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में भी सुरक्षा बलों की सतर्कता ने बड़ी अनहोनी टाल दी। अवनीरा गांव के एक बाग से लगभग छह किलो वजनी आईईडी बरामद कर उसे नियंत्रित विस्फोट में नष्ट कर दिया गया। यह साफ है कि गणतंत्र दिवस से पहले आम लोगों को निशाना बनाने की साजिश रची जा रही थी जिसे समय रहते विफल कर दिया गया। इसी बीच, कश्मीर में कुछ पत्रकारों को पुलिस द्वारा तलब किए जाने को लेकर बहस छिड़ गई है। कुछ संगठनों और दलों ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़ कर देखा है जबकि सुरक्षा एजेंसियों का रुख स्पष्ट है कि संवेदनशील माहौल में हर सूचना की जांच जरूरी है। देखा जाये तो जब आतंकवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो तब अफवाह और अधूरी जानकारी भी हथियार बन सकती है।

राहुल गांधी ने मनरेगा के लिए लोगों से एकजुट होने का आह्वान किया

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम' (मनरेगा) की जगह लाए गए 'विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम' को लेकर बृहस्पतिवार को भारतीय जनता पार्टी तथा केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और लोगों का आह्वान किया कि वे सरकार के इस कदम के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हों।

उन्होंने कांग्रेस के प्रकोष्ठ रचनात्मक कांग्रेस द्वारा आयोजित कार्यक्रम मनरेगा बचाओ मोर्चा में यह आरोप भी लगाया कि भाजपा एक ऐसा हिंदुस्तान चाहती है जहां एक राजा सारे फैसले करे।

राहुल गांधी ने कहा, मनरेगा की परिकल्पना गरीबों को रोजगार देने के अधिकार का कानून था... इसमें लोगों और मजदूरों की आवाज थी। इस योजना ने हर गरीब व्यक्ति को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी थी।"

उन्होंने कहा कि अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा इसे खत्म करना चाहते हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने निरस्त हो चुके कृषि कानूनों का उल्लेख करते हुए कहा कि किसानों ने दबाव डालकर कानूनों को रद्द करवाया था तथा उन्होंने मजदूरों को रास्ता दिखाया है।

राहुल गांधी ने दावा किया कि ये लोग (भाजपा) आधुनिक भारत के ढांचे को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मुझे मालूम है कि ये (भाजपा) डरपोक लोग हैं। अगर हम लोग एक साथ खड़े हो गए तो आप निर्णय लेंगे कि योजना का नाम क्या होगा और यह कैसे चलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ गरीबों को एकजुट होकर खड़ा होना पड़ेगा।

केजरीवाल, मान ने 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' की शुरुआत की

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बृहस्पतिवार को राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' की शुरुआत की जिसके तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपये तक का निःशुल्क चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। इस स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत राज्य के सभी 65 लाख परिवारों को शामिल किया गया है।

योजना का लाभ पंजाब का कोई भी निवासी उठा सकेगा, जिसके पास आधार कार्ड व मतदाता पहचान पत्र हैं। अधिकारियों के अनुसार, इस योजना में 2,500 से अधिक चिकित्सीय उपचार शामिल हैं और सरकारी अस्पतालों के साथ कुछ निजी अस्पतालों में भी इसका लाभ मिलेगा।

योजना की शुरुआत के बाद समारोह को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा, 'आज का दिन केवल पंजाब ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक है।' भगवंत मान सरकार के कार्यों की सराहना करते हुए केजरीवाल ने कहा कि पिछले चार वर्षों का यह कार्यकाल पंजाब के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इस अवसर पर आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, पंजाब के मंत्री अमन अरोड़ा और हरपाल सिंह चीमा भी मौजूद थे।

अंबाला में 1.90 करोड़ की ठगी मामले में भाजपा नेता गिरफ्तार

आलीशान कोठी और लग्जरी गाड़ियां देख दंग रह गई पुलिस

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। अंबाला कैंट में करोड़ों रुपये की ठगी के मामले में रेलवे पुलिस (जीआरपी) को बड़ी सफलता मिली है। अंबाला जीआरपी और बिहार एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में ठगी के एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। टीम ने बिहार के समस्तीपुर जिले में छापेमारी कर भाजपा के पूर्व जिला प्रवक्ता पंकज कुमार लाल समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस को आरोपियों की आलीशान कोठी, महंगी गाड़ियां और भारी मात्रा में नकदी व जेवरात मिले, जिससे ठगी के बड़े नेटवर्क की पुष्टि हुई है।

दरअसल, पंजाब निवासी जोशी नामक व्यक्ति ने अंबाला कैंट जीआरपी थाना में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उनसे 1 करोड़ 90 लाख रुपये ठगने का आरोप लगाया गया है। शिकायत में बताया गया है कि रुपये डबल करने और कर्ज की रकम पर भारी मुनाफा दिलाने का झांसा दिया गया

था। वहीं जांच के दौरान समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय थाना क्षेत्र निवासी पंकज कुमार लाल और उसके साथियों की संलिप्तता सामने आई। इसके बाद जीआरपी प्रभारी हरीश कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया और फिर बिहार के दलसिंहसराय अनुमंडल के अजनौल गांव में छापेमारी की गई। इस दौरान मुख्य आरोपी पंकज कुमार लाल के साथ उसके दो सहयोगियों कौशल और रजनीश को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि पंकज कुमार लाल पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड था तो वहीं कौशल और रजनीश भोले-भाले लोगों को झांसे में फंसाते थे। यह कार्रवाई जाली नोट डबलिंग रैकेट से जुड़े एक मामले में की गई है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 6 लाख रुपये नकद, करीब 30 लाख रुपए के सोने के आभूषण और एक सफेद रंग की लग्जरी इनोवा कार बरामद की है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि पूछताछ के दौरान इस गिरोह से जुड़े कई अन्य बड़े नामों और देश के विभिन्न हिस्सों में की गई ठगी की वारदातों का खुलासा हो सकता है।

अगरतला में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की प्रमुख परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन करेंगे सिंधिया

नई दिल्ली/अगरतला केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 23 से 25 जनवरी 2026 तक त्रिपुरा और असम के तीन दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सिंधिया दोनों राज्यों में विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन, शिलान्यास कार्यक्रमों तथा क्षेत्रीय दौरे में भाग लेंगे।

अपने उक्त प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री 23 जनवरी को अगरतला पहुँचेंगे और रवीन्द्र सताब्दिकी भवन, इंद्रनगर में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके पश्चात सिंधिया अगरतला सरकारी मेडिकल कॉलेज के मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य (एमसीएच) विंग तथा अगरतला सरकारी डेंटल कॉलेज का भ्रमण करेंगे और तत्पश्चात वह त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ (माताबाड़ी मंदिर) में दर्शन करेंगे।

24 जनवरी को सिंधिया उत्तर त्रिपुरा जिले के कदमतला का दौरा करेंगे, जहाँ वह ?78.53 करोड़ की अगरवुड (अगर) परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही सिंधिया उनाकोटी विरासत स्थल का भी भ्रमण करेंगे।

25 जनवरी को केंद्रीय मंत्री डुम्बुर में ?276.78 करोड़ की लागत वाली माताबाड़ी पर्यटन परिपथ परियोजना का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वह गुवाहाटी, असम प्रस्थान करेंगे, जहाँ सिंधिया बांस परियोजनाओं के शिलान्यास एवं उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेंगे तथा गुवाहाटी विश्वविद्यालय में आयोजित 'प्रतिदिन अचीवर अवॉर्ड्स, 2026' समारोह में शामिल होंगे।

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह दौरा पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास, स्थानीय संसाधनों के सशक्त उपयोग, रोजगार सृजन और सांस्कृतिक-पर्यटन संभावनाओं को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा।

नासिक एयर शो पर शुल्क से नाराज वायुसेना, कहा- देखने के लिए कोई एंट्री फीस नहीं; प्रशासन ने दी ये सफाई

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित एयर शो को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। वायुसेना ने एयर शो देखने के लिए लोगों से प्रवेश शुल्क वसूले जाने पर नाराजगी जताई है। वायुसेना ने साफ किया है कि देशभर में होने वाले एयर शो का मकसद युवाओं को प्रेरित करना और राष्ट्र से जुड़ाव बढ़ाना है, न कि पैसे कमाना। इस बयान के बाद जिला प्रशासन के फैसले पर सवाल उठने लगे हैं।

भारतीय वायुसेना ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि उसके संज्ञान में आया है कि नासिक में आयोजित एयर शो को देखने के लिए लोगों से एंट्री फीस ली जा रही है। वायुसेना ने स्पष्ट किया कि वह किसी भी एयर शो के लिए प्रवेश शुल्क नहीं लेती और न ही ऐसे आयोजनों से कोई आर्थिक लाभ उठाती है। वायुसेना ने इसे अपने उद्देश्य के विपरीत बताया है।

प्रशासन की सफाई

इस मामले पर संपर्क करने पर जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा कि जो शुल्क लिया गया, वह एयर शो देखने के लिए नहीं बल्कि पानी, नाश्ता और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए था। अधिकारी के मुताबिक टिकट व्यवस्था भीड़ नियंत्रण और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर की गई थी। प्रशासन का दावा है कि इसका मकसद अव्यवस्था रोकना था, न कि कार्यक्रम को व्यावसायिक बनाना।

पूर्व वायुसेना कर्मियों की आपत्ति

गंगापुर डैम के ऊपर आयोजित इस एयर शो में वायुसेना की सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम ने करतब दिखाए। शो देखने के लिए 200 रुपये से लेकर 800 रुपये तक की राशि वसूली गई। इस फैसले की वायुसेना के कई पूर्व अधिकारियों ने आलोचना की। उनका कहना है कि टिकट लगाने से एयर शो का असली मकसद ही खत्म हो जाता है, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम आम लोगों और युवाओं को मुफ्त में प्रेरित करने के लिए होते हैं।

कल भी होगा एयर शो

नासिक के जिला कलेक्टर आयुष प्रसाद ने पहले कहा था कि जमा की गई राशि महाराष्ट्र सैनिक कल्याण विभाग को दी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि फैसला जन सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया था। अधिकारियों के मुताबिक नासिक में एयर शो शुक्रवार को भी आयोजित किया जाएगा। वायुसेना के बयान के बाद अब इस मुद्दे पर प्रशासन के फैसले की दोबारा समीक्षा की मांग उठ रही है।

पश्चिम रेलवे द्वारा दो प्रमुख ट्रेनों के टर्मिनल एवं कोच संरचना में अस्थायी परिवर्तन

कर्णावती एक्सप्रेस बांद्रा टर्मिनस से ओरिजिनेट/टर्मिनेट होगी वंदे भारत एक्सप्रेस 20-कोच रेक के साथ चलेगी

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

पश्चिम रेलवे द्वारा दो प्रमुख ट्रेनों के टर्मिनल एवं कोच संरचना में अस्थायी परिवर्तन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत (i) ट्रेन संख्या 12933/12934 मुंबई सेंट्रल-वटवा/अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल कर्णावती एक्सप्रेस के टर्मिनल को मुंबई सेंट्रल से बांद्रा टर्मिनस स्थानांतरित तथा (ii) ट्रेन संख्या 22961/22962 मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस के कोचों की संख्या को अस्थायी रूप से 16 से बढ़ाकर 20 किया जा रहा है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ट्रेन संख्या 22961/22962 मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस में अस्थायी रूप से चार अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे। यह व्यवस्था 26.01.2026 से 07.03.2026 तक यात्रा प्रारंभ करने वाली यह ट्रेन 20-कोच रेक के साथ चलेगी।

श्री विनीत ने आगे बताया कि ट्रेन संख्या 12933/12934 बांद्रा टर्मिनस-वटवा/अहमदाबाद-बांद्रा टर्मिनस कर्णावती एक्सप्रेस अस्थायी रूप से मुंबई सेंट्रल के बजाय बांद्रा टर्मिनस से ही ओरिजिनेट/टर्मिनेट होगी। यह व्यवस्था 26.01.2026 से 07.03.2026 तक यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन के लिए लागू होगी। ट्रेन संख्या 12933 बांद्रा टर्मिनस से 13:55 बजे प्रस्थान करेगी, जबकि ट्रेन संख्या 12934 बांद्रा टर्मिनस पर 12:30 बजे पहुंचेगी। बोरीवली और वटवा/अहमदाबाद के बीच समय-सारणी में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

यात्रियों से अनुरोध है कि उपर्युक्त परिवर्तनों को ध्यान में रखें और अपनी यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनाएं। समय-सारणी, ठहराव एवं कोच संरचना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

प्लास्टिक प्रतिबंधात्मक अभियान के अंतर्गत 75 हजार रुपये का दंड वसूल किया गया तथा 44.5 किलो प्लास्टिक की थैलियां जब्त की गईं

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

नवी मुंबई शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से नागरिकों की सहभागिता के लिए लगातार जनजागरूकता की जा रही है तथा इसके साथ ही प्लास्टिक प्रतिबंधात्मक जांच एवं दंडात्मक कार्रवाई के अभियान पूरे क्षेत्र में चलाए जा रहे हैं। इस संबंध में केंद्रीय एवं महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा निर्देश दिए गए हैं, जिनके अनुसार एकल उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंध के तहत विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं।

इसी क्रम में 22 जनवरी 2026 को सभी विभागीय कार्यालय क्षेत्रों में विशेष रूप से फेरीवालों, बाजारों और दुकानों पर प्लास्टिक थैलियों एवं एकल उपयोग प्लास्टिक की जांच का अभियान प्रभावी रूप से चलाया गया। यह अभियान महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे के निर्देशानुसार, अतिरिक्त आयुक्त श्री सुनील पवार तथा घनकचरा प्रबंधन विभाग के उप आयुक्त डॉ. अजय गडदे के नियंत्रण में चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत 5 व्यावसायिकों से 25 हजार रुपये का दंड वसूल किया गया तथा 7 किलोग्राम प्लास्टिक थैलियों का भंडार जब्त किया गया। इसमें तुर्भे विभाग की कार्रवाई में 5 हजार रुपये का दंड वसूला गया और 2 किलोग्राम प्लास्टिक थैलियां जब्त की गईं, वहीं घणसोली विभाग की कार्रवाई में 10 हजार रुपये का दंड वसूला गया और 3.5 किलोग्राम प्लास्टिक थैलियां जब्त की गईं। इसके अलावा परिमंडल 2 की उड़नदस्ते द्वारा 2 व्यावसायिकों से 10 हजार रुपये का दंड वसूला गया और 1.5 किलोग्राम प्लास्टिक थैलियां जब्त की गईं।

इससे पहले भी जनवरी माह में 21 जनवरी तक 10 फेरीवालों एवं व्यावसायिकों के पास प्लास्टिक थैलियां पाए जाने पर उनसे कुल 50 हजार रुपये का दंड वसूला गया था तथा 37 किलो 500 ग्राम प्लास्टिक थैलियों का भंडार जब्त किया गया था। इसमें नेरूल विभाग की कार्रवाई में 2 व्यावसायिकों से 10 हजार रुपये का दंड वसूला गया और 1.50 किलोग्राम प्लास्टिक थैलियां जब्त की गईं, वाशी विभाग में एक व्यावसायिक से 5 हजार रुपये का दंड वसूला गया और 1 किलोग्राम प्लास्टिक थैलियां जब्त की गईं, तुर्भे विभाग में 4 व्यावसायिकों से 20 हजार रुपये का दंड वसूला गया और 18.500 किलोग्राम प्लास्टिक थैलियां जब्त की गईं, परिमंडल 1 की उड़नदस्ते द्वारा 5 हजार रुपये का दंड वसूला गया और 2.50 किलोग्राम प्लास्टिक थैलियां जब्त की गईं, वहीं परिमंडल 2 की उड़नदस्ते द्वारा 2 व्यावसायिकों से 10 हजार रुपये का दंड वसूला गया और 14 किलोग्राम प्लास्टिक थैलियां जब्त की गईं। इस प्रकार आज के अभियान में कुल 10 व्यावसायिकों से 50 हजार रुपये का दंड वसूला गया और 37.500 किलोग्राम प्लास्टिक थैलियों का भंडार जब्त किया गया।

प्लास्टिक के कारण मानव जीवन और पर्यावरण को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंच रहा है, इसलिए नागरिकों से अपील की जाती है कि वे अपने दैनिक उपयोग से एकल उपयोग प्लास्टिक को पूरी तरह समाप्त करें और इसके स्थान पर कपड़े की थैलियों का उपयोग करें। साथ ही व्यावसायिकों को भी सूचित किया गया है कि वे अपनी दुकानों और कार्यालयों में प्लास्टिक थैलियां तथा एकल उपयोग प्लास्टिक न रखें।

मध्य रेल ने बॉक्साइट और अकेशिया पल्प की लोडिंग शुरू करके अपने माल ढुलाई पोर्टफोलियो का विस्तार किया

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मध्य रेल ने बॉक्साइट और अकेशिया पल्प की लोडिंग शुरू करके अपने माल ढुलाई पोर्टफोलियो का विस्तार किया है। मध्य रेल के मुंबई मंडल ने दो नई वस्तुओं बॉक्साइट और आयातित ब्लीच्ड हार्डवुड क्राफ्ट अकेशिया पल्प की लोडिंग शुरू की है, जो माल ढुलाई की मात्रा बढ़ाने और मंडल के राजस्व में वृद्धि करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्तमान में मुंबई मंडल के कुल राजस्व का 33% माल ढुलाई से प्राप्त होता है।

मध्य रेल ने मुंबई मंडल के उरण गुड्स शेड से पहली रैक लोड करके बॉक्साइट की लोडिंग की सफल शुरुआत की। दिनांक 19 जनवरी, 2026 को मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड ने उरण गुड्स शेड से यूटीसीएम (मेसर्स राजश्री सीमेंट वर्क्स), मलखेड, दक्षिण मध्य रेलवे के लिए बॉक्साइट की पहली रैक लोड की। इस लोडिंग से प्रति रेक 52.38 लाख रुपये की माल ढुलाई आय प्राप्त हुई है और उरण गुड्स शेड से प्रति माह 2 से 3 रेक की अतिरिक्त लोडिंग की उम्मीद है। उरण गुड्स शेड 29 नवंबर, 2024 को आरंभ किया गया था और अब तक यहां से कुल 21 कार्बन ब्लैक फीड स्टॉक रेक लोड किए जा चुके हैं। इसके अलावा उरण गुड्स शेड में सीमेंट और क्लिंकर के 21 रेक अनलोड भी किए गए हैं। बॉक्साइट विशेष सीमेंटों के प्राथमिक घटक के रूप में उपयोग होता है और पारंपरिक सीमेंट को अधिक पर्यावरण अनुकूल और मजबूत बनाने के लिए एक टिकाऊ योजक के रूप में कार्य करता है। यह औद्योगिक अपशिष्ट अवशेष का उपयोग करता है और क्लिंकर उत्पादन से CO_2 उत्सर्जन को कम करता है।

मध्य रेल ने एक अन्य वस्तु आयातित ब्लीच्ड हार्डवुड क्राफ्ट अकेशिया पल्प की लोडिंग भी शुरू कर दी है, जिसे ब्राजील से आयात किया गया है। दिनांक 20 जनवरी, 2026 को मेसर्स इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड ने मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से डीपी वर्ल्ड रेल लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड को 1488 किलोमीटर की दूरी तक इस वस्तु की लोडिंग की। इससे मंडल की माल ढुलाई आय में कुल 37.79 लाख रुपये की वृद्धि हुई है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान मुंबई मंडल ने 17.07 मिलियन टन माल ढुलाई दर्ज की है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह 16.92 मिलियन टन थी। इसी वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 27 न्यू मॉडिफाइड गुड्स रेक लोड किए गए, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में केवल 6 रेक लोड किए गए थे, जो 350% की उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। दिसंबर 2025 में मुंबई मंडल ने 1.93 मिलियन टन माल ढुलाई दर्ज की। इसी माह में कुल 13 ऑटोमोबाइल रेक लोड किए गए, जो प्रति माह अब तक की सबसे अधिक न्यू मॉडिफाइड गुड्स लोडिंग है। दिसंबर 2025 में कुल 711 कंटेनर रेक लोड किए गए और औसतन प्रतिदिन 1538 वैगन लोड किए गए।

माल ढुलाई परिचालन में प्राप्त ये उपलब्धियां माल ढुलाई और राजस्व सृजन को बढ़ाने के लिए मध्य रेल की प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं और बॉक्साइट लोडिंग तथा अकेशिया पल्प की शुरुआत से भविष्य में राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान मिलने की उम्मीद है।

यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए मध्य रेल मुंबई से नागपुर/मडगांव 4 विशेष ट्रेन सेवा चलाएगा

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए मध्य रेल मुंबई से नागपुर और मडगांव के बीच 4 विशेष ट्रेन सेवाएं चलाएगा। ट्रेन सेवाओं की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए मध्य रेल छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई और नागपुर तथा लोकमान्य तिलक टर्मिनस और मडगांव के बीच विशेष ट्रेनें संचालित करेगा।

सीएसएमटी नागपुर सीएसएमटी विशेष 2 सेवा के अंतर्गत ट्रेन संख्या 02139 दिनांक 25.01.2026 को 00:20 बजे सीएसएमटी से प्रस्थान करेगी और उसी दिन 15:30 बजे नागपुर पहुंचेगी। वहीं ट्रेन संख्या 02140 दिनांक 25.01.2026 को 20:00 बजे नागपुर से प्रस्थान करेगी और अगले दिन 13:30 बजे सीएसएमटी पहुंचेगी। इस ट्रेन का ठहराव दादर, ठाणे, कल्याण, इगतपुरी, नाशिक रोड, मनमाड, जलगांव, भुसावल, मलकापुर, शेगांव, अकोला, मुर्तिजापुर, बडनेरा, धामनगांव और वर्धा में होगा। ट्रेन की संरचना में 1 एसी 2 टियर, 6 एसी 3 टियर, 9 शयनयान श्रेणी, 4 सामान्य द्वितीय श्रेणी, 1 सामान्य द्वितीय श्रेणी सह गार्ड ब्रेक वैन तथा 1 जेनरेटर वैन शामिल होगी, जो एलएचबी कोच की होगी।

एलटीटी मडगांव एलटीटी विशेष 2 सेवा के अंतर्गत ट्रेन संख्या 01129 दिनांक 25.01.2026 को 01:00 बजे एलटीटी से प्रस्थान करेगी और उसी दिन 12:00 बजे मडगांव पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 01130 दिनांक 25.01.2026 को 14:30 बजे मडगांव से प्रस्थान करेगी और अगले दिन 04:05 बजे एलटीटी पहुंचेगी। इस ट्रेन का ठहराव ठाणे, पनवेल, पेन, रोहा, मानगांव, वीर, खेड़, चिपलुन, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, आडवली, विलवडे, राजपुर रोड, वैभववाड़ी रोड, नंदगांव रोड, कंकवली, सिंधुदुर्ग, कुडाल और सावंतवाड़ी रोड पर होगा। ट्रेन की संरचना में 1 एसी 2 टियर, 3 एसी 3 टियर, 8 शयनयान श्रेणी, 4 सामान्य द्वितीय श्रेणी तथा 2 सामान्य द्वितीय श्रेणी सह गार्ड ब्रेक वैन शामिल होंगी, जो आईसीएफ कोच की होंगी।

ट्रेन संख्या 02139, 02140 और 01129 के लिए आरक्षण दिनांक 23.01.2026 से सभी पीआरएस केंद्रों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगा। अनारक्षित डिब्बों की बुकिंग सामान्य शुल्क पर यूटीएस के माध्यम से की जा सकती है। इन विशेष ट्रेनों के ठहराव और समय की विस्तृत जानकारी के लिए यात्री enquiry.indianrail.gov.in वेबसाइट पर जा सकते हैं या एनटीईएस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया ध्यान दें।

पश्चिम रेलवे विभिन्न गंतव्यों के लिए चलाएगी तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेनें

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा अतिरिक्त भीड़ को समायोजित करने के उद्देश्य से विशेष किराये पर 03 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इन ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार हैः

1) ट्रेन संख्या 09035/09036 बांद्रा टर्मिनस-उधना द्वि-साप्ताहिक स्पेशल (20 फेरे)

ट्रेन संख्या 09035 बांद्रा टर्मिनस-उधना स्पेशल प्रत्येक शुक्रवार एवं शनिवार को बांद्रा टर्मिनस से 09:00 बजे प्रस्थान करेगी तथा उसी दिन 15:05 बजे उधना पहुँचेगी। यह ट्रेन 30 जनवरी से 28 फरवरी, 2026 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09036 उधना-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल प्रत्येक गुरुवार एवं शुक्रवार को उधना से 15:45 बजे प्रस्थान करेगी तथा उसी दिन 21:35 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुँचेगी। यह ट्रेन 29 जनवरी से 27 फरवरी, 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में अंधेरी, बोरीवली, वसई रोड, विरार, वैतरणा, सफाले, केलवे रोड, पालघर, बोईसर, वानगांव, दहाणू रोड, घोलवड, बोर्डी रोड, उमरगाम रोड, संजान, भीलाड, करमबेली, वापी, वलसाड, बिलीमोरा तथा नवसारी स्टेशनों पर रुकेगी।

सके अतिरिक्त, ट्रेन संख्या 09035 भायंदर तथा ट्रेन संख्या 09036 अतुल, पारडी एवं उदवाडा स्टेशनों पर भी रुकेगी।

इस ट्रेन में स्लीपर क्लास एवं जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

2) ट्रेन संख्या 09561/09562 बांद्रा टर्मिनस-ओखा साप्ताहिक स्पेशल (10 फेरे)

ट्रेन संख्या 09561 बांद्रा टर्मिनस-ओखा स्पेशल प्रत्येक बुधवार को बांद्रा टर्मिनस से 05:50 बजे प्रस्थान करेगी तथा उसी दिन 22:50 बजे ओखा पहुँचेगी। यह ट्रेन 28 जनवरी से 25 फरवरी, 2026 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09562 ओखा-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल प्रत्येक मंगलवार को ओखा से 10:20 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 04:20 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुँचेगी। यह ट्रेन 27 जनवरी से 24 फरवरी, 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, सूरत, भरूच, वडोदरा, अहमदाबाद, विरमगाम, सुरेन्द्रनगर, राजकोट, हापा, जामनगर, खंभालिया तथा द्वारका स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में एसी-2 टियर, एसी-3 टियर, एसी-3 टियर (इकोनॉमी), स्लीपर क्लास एवं जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

3) ट्रेन संख्या 09005/09006 बांद्रा टर्मिनस-भिवानी सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल (10 फेरे)

ट्रेन संख्या 09005 बांद्रा टर्मिनस-भिवानी स्पेशल प्रत्येक बुधवार को बांद्रा टर्मिनस से 11:00 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 13:00 बजे भिवानी पहुँचेगी। यह ट्रेन 28 जनवरी से 25 फरवरी, 2026 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09006 भिवानी-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल प्रत्येक गुरुवार को भिवानी से 14:35 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 16:10 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुँचेगी। यह ट्रेन 29 जनवरी से 26 फरवरी, 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, पालघर, वापी, सूरत, वडोदरा, रतलाम, मंदसौर, नीमच, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बिजयानगर, नसीराबाद, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, दौसा, अलवर, रेवाड़ी, कोसली तथा चरखी दादरी स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में एसी-2 टियर, एसी-3 टियर, स्लीपर क्लास एवं जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 09035, 09036, 09561, 09562 एवं 09005 की बुकिंग सभी पीआरएस काउंटरों तथा आईआरसीटीसी वेबसाइट पर खुली है। ट्रेनों के ठहराव, समय एवं संरचना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

मध्य रेल

सोलापुर मंडल

ई–प्रोक्योरमेंट

संख्या SUR/Sr.DMM/T.No. 96255816 का कार्यालय, सोलापुर दिनांकः 20.01.2026 ई–टेंडर नोटिस

भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से मंडल स्टोर कार्यालय मध्य रेलवे, सोलापुर, निम्नलिखित कार्यों के लिए सक्षम, प्रतिष्ठित फर्मों/ठेकेदारों से रेलवे की ई–प्रोक्योरमेंट वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर ऑनलाइन ई–निविदाएं आमंत्रित करता है। **01. टेंडर नंबरः– 96255816, 02. विवरणः–** संलग्न तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार विद्युत चालित, रोटरी स्क्रू, एअर–कूल्ड, माइक्रोप्रोसेसर आधारित स्टेशनरी एअर कॉम्प्रेसर 500 CFM 10 Kg/cm2 की सप्लाई, इनस्टॉलेशन कमिशनिंग एवं टेस्ट करना। **03. मात्राः– 2 नग., 04. बयाना राशि (INR):**–Rs.116460.00 **www.ireps.gov.in पर निविदा बंद होने की तिथि और समय 02.02.2026 11:30 बजे के बाद** संभावित निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे निविदा समाप्ति की तिथि से पहले वेबसाइट पर बार–बार विजिट करते रहें ताकि इस निविदा के लिए जारी किए गए किसी भी परिवर्तन/शुद्धिपत्र पर ध्यान दिया जा सके। वेबसाइटः **www.ireps.gov.in.**

वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक

07 सोलापूर

खतरनाक व विस्फोटक सामान के साथ यात्रा करना दंडनीय अपराध है

मध्य रेल

सोलापुर मंडल

ई–प्रोक्योरमेंट

भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से मंडल स्टोर कार्यालय मध्य रेलवे, सोलापुर, निम्नलिखित कार्यों के लिए सक्षम, प्रतिष्ठित फर्मों/ठेकेदारों से रेलवे की ई–प्रोक्योरमेंट वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर ऑनलाइन ई–निविदाएं आमंत्रित करता है। **01. टेंडर नंबरः– 96265011, 02. विवरणः–** आरडीएसओ ड्राइंग संख्या टी–5919 ऑल्ट–2 (नवीनतम संशोधन) के अनुरूप माल निर्माण एवं इलैस्टिक रेल क्लिप MK-V की सप्लाई करना और ईआरसी क्रमांक टी–31–2021–पांचवें संशोधन (संशोधन 2 और नवीनतम संशोधन सहित) के लिए आईआरएस विनिर्देश के अनुरूप लोचदार रेल क्लिप एमके–वी का माल, निर्माण और आपूर्ति। (**नोटः** जहां भी नवीनतम संशोधन का प्रयोग किया गया है, उसका अर्थ निविदा बंद होने की वास्तविक तिथि तक के संशोधन होंगे।), **03. मात्राः**–120846 नग, **04. बयाना राशि (INR):**– Rs. 241480.00, **www.ireps.gov.in पर निविदा बंद होने की तिथि और समय 04.02.2026 11:30 बजे के बाद,** संभावित निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे निविदा समाप्ति की तिथि से पहले वेबसाइट पर बार–बार विजिट करते रहें ताकि इस निविदा के लिए जारी किए गए किसी भी परिवर्तन/शुद्धिपत्र पर ध्यान दिया जा सके। वेबसाइटः **www.ireps.gov.in.**

वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक

05 सोलापूर

खतरनाक व विस्फोटक सामान के साथ यात्रा करना दंडनीय अपराध है

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत महाराष्ट्र में योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन- अध्यक्ष डॉ. एस. पी. कात्याल

मुंबई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम - 2013 के अंतर्गत राज्य में लागू की जा रही सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्कूल पोषण योजना तथा राष्ट्रीय एकीकृत बाल विकास सेवा योजना जैसी तीन महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावी एवं संतोषजनक है, ऐसा मत हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एस. पी. कात्याल ने व्यक्त किया।

अध्यक्ष कात्याल ठाणे जिला कलेक्टर कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उपस्थित थे। इस बैठक में राज्य खाद्य आयोग मुंबई के संयुक्त सचिव एवं सदस्य सचिव अत्राम, सचिव पी. एफ. गांगवे तथा ठाणे जिले के आपूर्ति, शिक्षा एवं महिला व बाल विकास विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

इस अवसर पर अध्यक्ष कात्याल ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थियों को उपलब्ध कराए जा रहे खाद्यान्न, पोषण आहार एवं बाल कल्याण सेवाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। साथ ही योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे उपायों की समीक्षा कर विभागवार सुझाव भी दिए।

बैठक के बाद अध्यक्ष कात्याल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत ठाणे की एक उचित मूल्य दुकान का दौरा कर वास्तविक वितरण प्रक्रिया का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने एक आंगनवाड़ी केंद्र का भी दौरा कर बच्चों के लिए संचालित सेवाओं की समीक्षा की। इसके अतिरिक्त उन्होंने 'अक्षयपात्र' योजना के अंतर्गत इस्कॉन द्वारा संचालित केंद्रीय रसोई का भी दौरा किया तथा विद्यालयों में वितरित किए जाने वाले मध्यान्ह भोजन की उत्पादन प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की।

बैठक एवं क्षेत्रीय निरीक्षण के पश्चात अध्यक्ष एस. पी. कात्याल ने संतोष व्यक्त किया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम - 2013 के अंतर्गत राज्य में सभी योजनाओं का सुचारु एवं अच्छे ढंग से क्रियान्वयन किया जा रहा है तथा संबंधित यंत्रणाओं की सराहना की।

मध्य रेल

नागपुर मंडल

ई–निविदा सूचना संख्याः CR-NGP-M-20-DT-20-01-2026

कार्य का नामः– "एक साल की अवधि के लिए नागपुर डिवीजन के अजनी डिपो मे लिस्टर ट्रक, फोर्क लिफ्ट आदि जैसे सामग्री प्रबंधन उपकरणों का संचालन" और चिन्हित क्षेत्रों में अजनी यार्ड पाथवे की सफाई, मलबे का संग्रह तथा डम्पिंग का कार्य"। **कार्य का स्थानः**– नागपुर डिवीजन के अजनी डिपो एवं अजनी यार्ड पाथवे। **कार्य कि अवधिः**– एक सात्र।, **कार्य का अनुमानित मूल्यः**– रु. 43,54,406.20 (रुपये तैंतालिस लाख, चौवन हजार, चार सौ छह रुपये और बीस पैसे मात्र)।, **निविदा की सुरक्षाः**– रु. 87,100.00 (रुपये सतासी हज़ार एक सौ रुपये मात्र)।, **निविदा दस्तावेज का मूल्यः**– कुछ नहीं।, **निविदा बंद होने की अंतिम तारीख तथा समयः**– 11.02.2026 को 12:30 बजे।, विस्तृत जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर लॉग ऑन करे।

वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर

30 मध्य रेल, नागपुर

खतरनाक व विस्फोटक सामान के साथ यात्रा करना दंडनीय अपराध है

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पहल

लंबित मामलों के निपटारे से त्वरित न्याय प्राप्त हो रहा है।

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

राज्य सरकार 'सभी के लिए न्याय, त्वरित न्याय' के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पहल और मार्गदर्शन में न्याय व्यवस्था की कड़ियों में मौजूद कमियों को दूर किया जा रहा है, ताकि तेज़ गति से न्याय मिल सके। नए आपराधिक कानून के अंतर्गत त्वरित न्याय को प्राथमिकता दी गई है और उसी के अनुसार न्यायिक सहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में लंबित मामलों का निपटारा किया जा रहा है। इसके कारण न्याय प्रक्रिया और अधिक तेज़ हो गई है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने न्यायिक सहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाला संचालनालय के अंतर्गत लंबित मामलों का तत्काल निपटारा करने के लिए विशेष अभियान लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नियमित समीक्षा के माध्यम से इन लंबित मामलों के निपटारे की प्रक्रिया को भी तेज़ किया। 2025 में संचालनालय की प्रयोगशालाओं में एक लाख 81 हजार मामले लंबित थे। साथ ही दो लाख 94 हजार मामले प्राप्त हुए थे। विशेष अभियान लागू कर दिसंबर

2025 के अंत तक तीन लाख 96 हजार 879 मामलों का निपटारा किया गया, जिससे लंबित मामलों की संख्या घटकर 79 हजार 542 रह गई।

इस विशेष अभियान के अंतर्गत सभी विभागों के प्रचलित मानकों को बढ़ाकर संचालनालय के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक अतिरिक्त कार्य समय दिया गया तथा सरकारी अवकाश के दिनों में भी कार्य कर लंबित मामलों का निपटारा किया गया। यद्यपि संचालनालय में कार्यरत मानव संसाधन की क्षमता कम से कम दो लाख से दो लाख 15 हजार मामलों के निपटारे की है, फिर भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सुझाव के अनुसार तीन लाख 96 हजार 879 मामलों का निपटारा किया गया। लंबित मामलों में से संचालनालय एक लाख 02 हजार 413 अतिरिक्त मामलों का समाधान करने में सफल रहा। दिसंबर 2025 तक पारंपरिक फॉरेंसिक विभाग ने लंबित मामलों में से तीन लाख 96 हजार 275 मामलों का निपटारा किया है। इस विभाग में 27 हजार 524 नए मामले प्राप्त हुए हैं और फरवरी 2026 से मामले प्राप्त होने वाले दिन से ही उनके विश्लेषण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे प्रतिदिन लंबित रहने वाले मामलों की समस्या समाप्त होगी और पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। कंप्यूटर अपराध विभाग, साइबर, ध्वनि एवं ऑडियो रिकॉर्डिंग विभाग के लंबित मामलों का भी शीघ्र निपटारा किया जा रहा है।

न्याय प्रक्रिया के तेज़ होने से पीड़ितों को न्याय के लिए वर्षों तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। न्यायिक सहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाला संचालनालय की त्वरित न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी कारण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संचालनालय को और अधिक सक्षम बनाने पर जोर दिया है। राज्य के प्रत्येक उपविभागीय पुलिस अधिकारी कार्यालय को एक मोबाइल फॉरेंसिक वैन प्रदान की जा रही है। इन सभी प्रयासों से न्याय प्रक्रिया को गति देने में सहायता मिल रही है।

भारत निर्वाचन आयोग के 'ईसीआईनेट' डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन

मुंबई। भारत निर्वाचन आयोग ने इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (आईआईसीडीईएम)-2026 के दौरान एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म 'ईसीआईनेट' का उद्घाटन किया। यह तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 21 से 23 जनवरी 2026 के दौरान भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है।

'ईसीआईनेट' की संकल्पना मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की है और निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू तथा डॉ. विवेक जोशी के सहयोग से इसका विकास किया गया है। इसके विकास की घोषणा मई 2025 में की गई थी।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म कानूनी ढांचे के भीतर विकसित किया गया है और 22 अनुसूचित भाषाओं तथा अंग्रेज़ी में उपलब्ध है। उन्होंने विश्व भर की निर्वाचन प्रबंधन संस्थाओं से भी अपील की कि वे अपने-अपने घरेलू कानूनों और स्थानीय भाषाओं के अनुरूप इसी तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए भारत के साथ सहयोग करें।

निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू ने कहा कि ईसीआईनेट से चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और निर्वाचन संस्थाओं में विश्वास मजबूत होगा, साथ ही प्रक्रिया की प्रभावी निगरानी, तेज़ निर्णय-निर्माण और सूचनाओं के त्वरित प्रसार में मदद मिलेगी। डॉ. विवेक जोशी ने कहा कि यह सम्मेलन निर्वाचन संस्थाओं को प्रौद्योगिकी और डिजिटल नवाचारों के उपयोग में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को जानने का अवसर प्रदान करेगा।

अपनी प्रस्तुति में सूचना प्रौद्योगिकी महानिदेशक डॉ. सीमा खन्ना ने बताया कि ईसीआईनेट साइबर सुरक्षा का मुख्य स्तंभ है। उन्होंने कहा कि आज प्रौद्योगिकी केवल सहायक भूमिका नहीं निभा रही है, बल्कि नीति को सक्षम बनाने वाली बन गई है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि 'ईसीआईनेट' से चुनावों में पारदर्शिता, दक्षता, विश्वसनीयता और जन-विश्वास में वृद्धि होगी।

ईसीआईनेट दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव सेवा प्लेटफॉर्म है, जिसमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के निर्वाचन आयोग के 40 से अधिक ऐप्स और पोर्टल्स को एकीकृत किया गया है। यह प्लेटफॉर्म भारतीय संविधान, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951, मतदाता पंजीकरण नियम 1960 तथा निर्वाचन आचरण नियम 1961 के पूर्ण अनुपालन में विकसित किया गया है।

इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिकों, उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों और निर्वाचन अधिकारियों को एक ही सुरक्षित प्रणाली पर जोड़ा गया है। यहां मतदाता पंजीकरण, मतदाता सूची खोज, आवेदन की स्थिति जांच, उम्मीदवारों की जानकारी, निर्वाचन अधिकारियों से संपर्क, बीएलओ के साथ कॉल बुकिंग, ई-ईपीआईसी डाउनलोड, मतदान प्रवृत्ति और शिकायत निवारण जैसी अनेक सेवाएं उपलब्ध हैं। ईसीआईनेट का बीटा संस्करण 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव और विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान सफलतापूर्वक उपयोग किया गया था। नागरिकों के सुझावों पर विचार करने के बाद इसे अंतिम रूप दिया गया। अब तक इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक पंजीकरण आवेदन संसाधित किए जा चुके हैं, जिनमें औसतन प्रतिदिन 2.7 लाख आवेदन निपटाए जा रहे हैं। 11 लाख से अधिक बूथ लेवल अधिकारी पंजीकृत किए गए हैं और 150 करोड़ से अधिक दस्तावेजों का डिजिटलीकरण किया गया है। इसके साथ ही यह प्रणाली क्षेत्र स्तर के कर्मचारियों के कार्य की प्रभावी निगरानी की सुविधा भी प्रदान करती है, ऐसा भारत निर्वाचन आयोग ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया।

गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर महाराष्ट्र की सांस्कृतिक गौरवगाथा का प्रदर्शन होगा

गणेशोत्सव : आत्मनिर्भरता का प्रतीक 'चित्ररथ' तैयार

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी के कर्तव्य पथ पर होने वाली भव्य परेड के लिए महाराष्ट्र का चित्ररथ पूरी तरह तैयार है। इस वर्ष राज्य 'गणेशोत्सव : आत्मनिर्भरता का प्रतीक' इस संकल्पना पर आधारित चित्ररथ प्रस्तुत करेगा। राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' की 150वीं वर्षगांठ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में इस वर्ष का समारोह विशेष महत्व का है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयेन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे, और उनकी उपस्थिति में परेड में शामिल होने वाला महाराष्ट्र का यह चित्ररथ राज्य की दीर्घ सांस्कृतिक परंपरा और बढ़ती आर्थिक शक्ति को पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करेगा। यह चित्ररथ प्रभावी रूप से दर्शाता है कि जिस आंदोलन की शुरुआत लोकमान्य तिलक ने सार्वजनिक गणेशोत्सव के माध्यम से की थी, वही आंदोलन आज आधुनिक भारत को 'आत्मनिर्भर' बना रहा है। गणेशोत्सव के माध्यम से होने वाला करोड़ों का आर्थिक कारोबार, मूर्तिकारों और सजावट से जुड़े कारीगरों को मिलने वाला स्थायी रोजगार तथा उससे निर्मित आर्थिक श्रृंखला इस चित्ररथ के केंद्र में है। महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2025 से सार्वजनिक गणेशोत्सव को 'राज्य महोत्सव' के रूप में मनाना शुरू किया है और यह चित्ररथ इस बात को रेखांकित करता है कि यह उत्सव केवल सांस्कृतिक ही नहीं, बल्कि पर्यावरणीय और आर्थिक आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देता है।

चित्ररथ कैसा होगा?

महाराष्ट्र के इस चित्ररथ का स्वरूप अत्यंत कलात्मक और आकर्षक है। चित्ररथ के अग्रभाग में महाराष्ट्र की ऊर्जा का प्रतीक भव्य ढोल और उसे बजाती पारंपरिक वेशभूषा में सजी एक महिला राज्य की सशक्त नारी शक्ति को प्रदर्शित करेगी। चित्ररथ के मध्य भाग में गणेश की सुंदर मूर्ति गढ़ता हुआ एक मूर्तिकार और विसर्जन के लिए जाते हुए गणेश भक्त को दर्शाया गया है। चित्ररथ के अंतिम भाग में महाराष्ट्र के प्रमुख तीर्थस्थल अष्टविनायक मंदिर की भव्य प्रतिकृति बनाई गई है तथा अन्य सांस्कृतिक पहलुओं को भी सूक्ष्मता के साथ प्रस्तुत किया गया है। चित्ररथ के दोनों ओर पारंपरिक नौवारी साड़ियों में सजी महिलाओं की शोभायात्रा भी दिखाई देगी।

इस वर्ष का समारोह 'जनभागीदारी' की संकल्पना पर आधारित है और परेड के बाद 26 से 31 जनवरी के दौरान लाल किले में आयोजित होने वाले 'भारत पर्व' में भी देशवासी महाराष्ट्र की सांस्कृतिक समृद्धि और आत्मनिर्भरता की यात्रा का आनंद ले सकेंगे।

महाराष्ट्र में गुटखा पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए अलग कानून लाया जाएगा- मंत्री नरहरि जिरवाल

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

महाराष्ट्र में गुटखा और इसी प्रकार के प्रतिबंधित पदार्थों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के लिए अलग कानून बनाया जाएगा। खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री नरहरि जिरवाल ने गुजरात में लागू शराबबंदी कानून की तर्ज पर इस विषय का अध्ययन कर आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद कानून का मसौदा तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

गुटखा और प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों पर कानून के सख्त क्रियान्वयन के अनुरूप मंत्रालय में खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री जिरवाल की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में वैद्यकीय शिक्षा एवं औषधि विभाग के प्रधान सचिव धीरज कुमार, खाद्य एवं औषधि प्रशासन आयुक्त श्रीधर दुबे पाटिल, विधि एवं न्याय विभाग के संयुक्त सचिव महेंद्र जाधव, गृह विभाग के संयुक्त सचिव राहुल कुलकर्णी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सागर पाटिल तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

राज्य में गुटखा और प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों की अवैध बिक्री रोकने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा गृह विभाग की संयुक्त टीम गठित करने और अवैध गुटखा विक्रेताओं के खिलाफ 'मकोका' के तहत कार्रवाई करने का प्रस्ताव रखा था। इसी पृष्ठभूमि में मंत्री जिरवाल ने गुजरात के शराबबंदी कानून की तर्ज पर गुटखा प्रतिबंध के लिए अलग कानून तैयार कर आगामी बजट सत्र में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री जिरवाल ने कहा कि राज्य में गुटखा और इसी प्रकार के प्रतिबंधित पदार्थों का उत्पादन, वितरण और बिक्री प्रतिबंधित है। अवैध व्यापार के खिलाफ और सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए गुटखा विक्रेताओं पर 'मकोका' लागू करने से संबंधित कानून में आवश्यक संशोधन कर उसे और अधिक कड़ा बनाया जाएगा तथा गुटखा व्यवसाय से जुड़े अपराधों को 'मकोका' के दायरे में लाया जाएगा।

राज्य भर में गुटखा की बिक्री और परिवहन के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है और विभिन्न जिलों में अनेक प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही व्यापक जनजागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री जिरवाल ने निर्देश दिए कि गुटखा और इसी प्रकार के प्रतिबंधित पदार्थों पर 'मकोका' लागू करने के लिए आवश्यक प्रावधानों के संबंध में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, गृह विभाग और विधि एवं न्याय विभाग के साथ समन्वय कर सुझाव प्रस्तुत करे।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री जिरवाल ने यह भी कहा कि विशेष रूप से स्कूलों और कॉलेजों के परिसर में ऐसे प्रतिबंधित पदार्थों की बिक्री के खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

संस्कृति, मराठी भाषा और तकनीक का समन्वय समय की आवश्यकता- सांस्कृतिक कार्य मंत्री एड. आशीष शेलार

पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी में 'व्याख्यानमाला' का शुभारंभ

मुंबई। सार्वजनिक उत्सव, व्याख्यानमालाएं और सांस्कृतिक गतिविधियां समाज, संस्कृति, राष्ट्र और एकता को जोड़ने का प्रभावी माध्यम हैं। जिस प्रकार सार्वजनिक गणेशोत्सव की एक समृद्ध परंपरा है, उसी तरह बौद्धिक समृद्धि प्रदान करने वाली व्याख्यानमालाओं की परंपरा को आगे बढ़ाने का निर्णय राज्य शासन ने लिया है और यह उसका पहला प्रयास है। छत्रपति शिवाजी महाराज के 12 किलों को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने की प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए मंत्री शेलार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सक्रिय प्रयासों के कारण यह ऐतिहासिक निर्णय संभव हो सका। महाराज की 'रयते का राजा' और 'उपभोगशून्य स्वामी' की संकल्पना को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने में महाराष्ट्र को सफलता मिली है, इस

यह विचार सांस्कृतिक कार्य एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार ने व्यक्त किए।

सांस्कृतिक कार्य विभाग के अंतर्गत पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी द्वारा पहली बार आयोजित इस व्याख्यानमाला का शुभारंभ आज एडवोकेट आशीष शेलार की उपस्थिति में संपन्न हुआ। उद्घाटन भाषण में बोलते हुए उन्होंने कहा कि संस्कृति और तकनीक के संतुलित समन्वय से ही समाज को सही दिशा दी जा सकती है।

इस अवसर पर पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी की संचालक मीनल जोगलेकर, वरिष्ठ लेखक, विचारक एवं अभ्यासक अच्युत गोडबोले, सलाहकार समिति के सदस्य डॉ. शिरीष ठाकूर तथा सोनिया परचुरे उपस्थित थे।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और तकनीक के बढ़ते प्रभाव पर बोलते हुए मंत्री शेलार ने कहा कि आज प्रत्येक नागरिक का तकनीक से सीधा संबंध है। मोबाइल, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से बड़ी मात्रा में जानकारी एकत्रित हो रही है। ऐसे में तकनीक का सुरक्षित, सकारात्मक और जिम्मेदार उपयोग समझना अत्यंत आवश्यक है। इस विषय पर अच्युत गोडबोले जैसे विद्वान वक्ताओं का मार्गदर्शन समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा उन्होंने कहा।

पर उन्होंने गर्व व्यक्त किया।

मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा मिलने के बाद साहित्य, लोककला, लोकसंगीत, विज्ञान, तकनीक और विभिन्न क्षेत्रों में मराठी सृजन को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य शासन प्रतिबद्ध है। राज्य में वर्षभर 1200 से अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जो महाराष्ट्र की सांस्कृतिक 'सॉफ्ट पावर' का प्रतीक हैं, ऐसा भी उन्होंने कहा।

पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी की संचालक मीनल जोगलेकर ने कहा कि गणेशोत्सव को राज्य महोत्सव का दर्जा मिलने के बाद पूरे महाराष्ट्र में विविध सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में यह व्याख्यानमाला आयोजित की गई है।

इस व्याख्यानमाला के अंतर्गत 22 जनवरी को वरिष्ठ लेखक, विश्लेषक एवं अभ्यासक अच्युत गोडबोले 'एआई तकनीक और कला जगत', 23 जनवरी को पुरातत्वविद एवं पुरातत्व तथा वस्तुसंग्रहालय संचालनालय के संचालक डॉ. तेजस गर्गे 'छत्रपति शिवाजी महाराज के किलों के यूनेस्को नामांकन की रोमांचक यात्रा' तथा 24 जनवरी को मराठी भाषा विभाग एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग के सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी 'अभिजात मराठी: इतिहास, वर्तमान और भविष्य' विषय पर संवाद करेंगे।

महाराष्ट्र के CM इतने लाचार क्यों?: मंत्री के फरार बेटे पर HC की तल्ख टिप्पणी, पूछा- क्या राज्य में कानून है

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार पर तीखी टिप्पणी करते हुए पूछा कि क्या राज्य में कानून का राज है? कोर्ट ने सवाल किया कि क्या मुख्यमंत्री इतने लाचार हैं कि वह एक ऐसे मंत्री के खिलाफ कुछ नहीं कह सकते, जिसका बेटा आपराधिक मामले में नाम आने के बाद से फरार है।

अदालत शिवसेना मंत्री भारत गोगावले के बेटे विकास गोगावले की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जस्टिस माधव जामदार ने तीखी टिप्पणी में कहा कि मंत्रियों के बच्चे अपराध करते हैं और खुलेआम घूमते हैं लेकिन पुलिस उन्हें ढूंढ नहीं पाती। बता दें कि विकास को महाड नगर परिषद चुनाव के दौरान प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प से जुड़े मामले में आरोपी बनाया गया है।

सरकार ने दिया सरेंडर का भरोसा

कोर्ट की फटकार के बाद, सरकार ने आश्वासन दिया कि मंत्री यह सुनिश्चित करेंगे कि उनका बेटा एक दिन के भीतर आत्मसमर्पण कर दे। विकास गोगावले ने सत्र अदालत द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद हाई कोर्ट का रुख किया, लेकिन वह अभी भी फरार है।

क्या मुख्यमंत्री इतने लाचार हैं?

जस्टिस माधव जामदार ने कहा कि क्या राज्य के मुख्यमंत्री इतने लाचार हैं कि वह एक मंत्री के खिलाफ भी कुछ

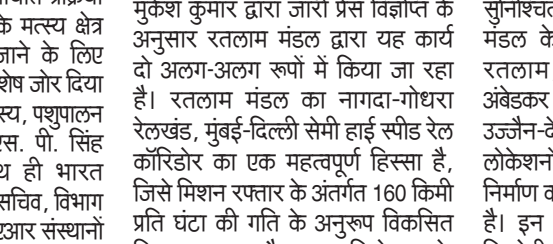

नहीं कहते? मंत्रियों के बच्चे अपराध करते हैं और खुलेआम घूमते हैं और वे अपने माता-पिता के संपर्क में रहते हैं लेकिन पुलिस उन्हें ढूंढ नहीं पाती? जज ने यह भी सवाल किया कि क्या राज्य में कानून-व्यवस्था और कानून का राज कायम है।

महाधिवक्ता मिलिंद साठे ने कहा कि मंत्री गोगावले अपने बेटे से बात करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि वह शुक्रवार को पुलिस के सामने सरेंडर कर दे। हाई कोर्ट ने कहा कि उसे कल सुनवाई से पहले सरेंडर करने के लिए कहें। कोर्ट ने पहले चेतावनी दी थी कि अगर पुलिस विकास गोगावले को पकड़ने में विफल रहती है तो उसे आदेश पारित करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जस्टिस जामदार ने आगे कहा कि आप (पुलिस) पर दबाव हो सकता है, अदालत पर नहीं।

यह है पूरा मामला

यह मामला रायगड जिले के महाड में नगर परिषद चुनाव के दौरान दो गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प से जुड़ा है। यह झड़प 2 दिसंबर को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के समर्थकों के बीच हुई थी। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराईं और क्रॉस-एफआईआर दर्ज की गईं। एक एफआईआर में विकास गोगावले, उनके चचेरे भाई महेश गोगावले और उनके समर्थकों का नाम है। दूसरी एफआईआर में एनसीपी नेता और पूर्व विधायक माणिक जगताप के बेटे श्रीयांश जगताप का नाम है। हाई कोर्ट ने बाद में श्रीयांश जगताप को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया।

झींगा उत्पादन और मत्स्य विकास के लिए दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक

मत्स्य मंत्री नितेश राणे की उपस्थिति

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

देश में मत्स्य क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन लाने और झींगा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के उद्देश्य से केंद्रीय मत्स्य मंत्रालय की ओर से एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह (ललन सिंह) ने की। बैठक में महाराष्ट्र के मत्स्य एवं बंदरगाह विकास मंत्री नितेश राणे ने महाराष्ट्र में मत्स्य विकास की स्थिति तथा झींगा उत्पादकों को आ रही समस्याओं की विस्तृत जानकारी दी। बैठक में मुख्य रूप से एसपीएफ झींगा ब्रूडस्टॉक, पीपीएल से संबंधित विभिन्न कानूनी एवं तकनीकी पहलुओं तथा जीवित आहार के आयात से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। झींगा उत्पादन में सतत विकास सुनिश्चित करते हुए सख्त जैव सुरक्षा मानकों के पालन, आयात प्रक्रिया को सरल बनाने तथा देश के मत्स्य क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर विशेष जोर दिया गया। इस बैठक में केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री प्रो. एस. पी. सिंह बघेल उपस्थित रहे। साथ ही भारत सरकार के मत्स्य विभाग के सचिव, विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, आईसीएआर संस्थानों के प्रख्यात वैज्ञानिक, एमपीईडीए और सीएए के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।

रतलाम मंडल में ट्रैक साइड फेंसिंग से बढ़ेगी ट्रेनों की गति, संरक्षा एवं सुरक्षा

रतलाम। पश्चिम रेलवे का रतलाम मंडल यात्रियों की सुविधा के साथ-साथ ट्रेनों की गति, संरक्षा एवं सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाए रखने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में रतलाम मंडल द्वारा ट्रैक साइड फेंसिंग (बाउंड्री वॉल/सेफ्टी फेंसिंग) का कार्य व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री मुकेश कुमार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार रतलाम मंडल द्वारा यह कार्य दो अलग-अलग रूपों में किया जा रहा है। रतलाम मंडल का नागदा-गोधरा रेलखंड, मुंबई-दिल्ली सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे मिशन रफ्तार के अंतर्गत 160 किमी प्रति घंटा की गति के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत ट्रेनों की गति बनाए रखने तथा रेलवे ट्रैक पर पशुओं के आने से होने वाले रेल एवं किसानों के नुकसान को रोकने के उद्देश्य से नागदा-गोधरा रेलखंड के चिन्हित स्थानों पर लगभग 98 किलोमीटर रेलखंड को बाउंड्री वॉल से सुरक्षित करने का कार्य आरंभ किया गया था जिसे पूर्ण कर लिया गया है। इससे न केवल ट्रेनों का परिचालन सुरक्षित हुआ है, बल्कि पशु मालिकों को भी सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। इसके अतिरिक्त रतलाम मंडल के चंदेरिया-मंदसौर, मंदसौर-रतलाम, मंदसौर-इंदौर, इंदौर-डॉ. अंबेडकर नगर-खंडवा, नागदा-भोपाल तथा उज्जैन-देवास-इंदौर रेलखंडों के चिन्हित लोकेशनों पर सेफ्टी फेंसिंग/बाउंड्री वॉल निर्माण का कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है। इन रेलखंडों में कुल लगभग 501 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में बाउंड्री वॉल का निर्माण प्रस्तावित है। गत वर्ष के दौरान लगभग 127 किलोमीटर क्षेत्र में बाउंड्री वॉल का निर्माण किया गया, जबकि वर्ष 2025-26 में अब तक लगभग 80 किलोमीटर क्षेत्र में बाउंड्री वॉल का निर्माण पूरा किया जा चुका है। इंदौर-देवास-उज्जैन-भोपाल रेलखंड पर वंदे भारत ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण खंड पर सुरक्षा , संरक्षा को ध्यान में रखते हुए बाउंड्री वॉल निर्माण का कार्य तेज गति से प्रगति पर है। रतलाम मंडल के सभी चिन्हित क्षेत्रों में बाउंड्री वॉल निर्माण होने से रेलवे ट्रैक पर पालतू एवं जंगली जानवरों की आवाजाही रुकेगी, ट्रेनों निर्बाध रुप से अपने अधिकतम गति से चलेगी, ट्रैक के आस-पास के किसानों के पशुधन का नुकसान बचेगा, ट्रेनों का संरक्षित संचालन होगा जिससे समयपालनता में भी सुधार होगा तथा यात्री निर्धारित समय में अपने गंतव्य स्टेशन तक पहुँच सकेंगे।

सम्पादकीय

विकास की आड़ में प्रकृति की सुरक्षा दीवार को तोड़ने की तैयारी, क्या अरावली को खोकर भारत आगे बढ़ पाएगा?

देश में अवैध और अवैज्ञानिक तरीके से खनन तथा इसके पर्यावरण पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। ये तर्क सही हो सकते हैं कि खनन गतिविधियां विकास प्रक्रिया का हिस्सा हैं, लेकिन क्या पर्यावरण की कीमत पर विकास की राह तलाशना उचित है? पिछले कुछ दिनों से चर्चा में रहे अरावली पर्वत-श्रृंखला के मसले को लेकर यह बहस जोर पकड़ रही है कि अगर कोई प्राकृतिक संरचना किसी क्षेत्र के लिए जीवन-धारा और सुरक्षा दीवार के रूप में खड़ी है, तो क्या उसका संरक्षण जरूरी नहीं है! हाल के वर्षों में अरावली क्षेत्र में खनन गतिविधियां बढ़ी हैं और इससे होने वाले नुकसान को लेकर उठी आवाज की अनदेखी हुई है। यही वजह है कि बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्पष्ट किया कि अरावली में खनन और इससे संबंधित मुद्दों की व्यापक एवं समग्र जांच जरूरी है तथा इसके लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाएगी। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि अरावली क्षेत्र में अवैध खनन से पर्यावरण को अपूरणीय क्षति हो सकती है। गौरतलब है कि पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि आसपास की जमीन से कम से कम सौ मीटर ऊंचे हिस्से को ही अरावली पहाड़ी के तौर पर माना जाएगा। अदालत की इस नई परिभाषा के बाद यह आशंका पैदा हो गई थी कि अगर सौ मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर खनन, निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों के रास्ते खुलेंगे, तो इसके बाद समूचे इलाके के पारिस्थितिकी तंत्र पर गंभीर पर्यावरणीय प्रभाव पड़ सकते हैं।

क्योंकि, पहाड़ियों के बीच पांच सौ मीटर की दूरी के मानक से अरावली का बड़ा हिस्सा पर्यावरण संरक्षण से बाहर हो सकता था। हालांकि, बाद में शीर्ष अदालत ने अपने इस फैसले को स्थगित करते हुए कहा था कि इस मामले में कुछ गंभीर अस्पष्टताओं का समाधान जरूरी है। अब न्यायालय ने सरकार को चार सप्ताह के भीतर खनन क्षेत्र के विशेषज्ञ और वैज्ञानिकों के नाम सुझाने का निर्देश दिया है, ताकि विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया जा सके। मगर यह पहलू भी महत्त्वपूर्ण है कि विशेषज्ञों की समिति बिना किसी दबाव और निष्पक्षता से अध्ययन कर अपने सुझाव सामने रखे। इस चिंता को दूर करने के लिए शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कहा है कि यह समिति उसके निर्देशन और निगरानी में कार्य करेगी।

दरअसल, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात से लेकर दिल्ली तक के सैकड़ों किलोमीटर इलाके में फैली अरावली पर्वत-श्रृंखला को उत्तर भारत में पर्यावरण को संतुलित रखने की लिहाज से एक प्राकृतिक दीवार के रूप में देखा जाता है। मगर पिछले कुछ वर्षों से अरावली क्षेत्र में जिस तरह पत्थर, रेत और अन्य संसाधनों की पूर्ति के लिए खनन गतिविधियां बढ़ी हैं, उससे इलाके के पर्यावरण पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि अरावली के आसपास के क्षेत्र में भूजल स्तर को सामान्य बनाए रखने, रेगिस्तान बनने से रोकने और लोगों की आजीविका बचाने के लिए इसका संरक्षण जरूरी है। इसे न केवल पर्यावरणीय, बल्कि भूगर्भीय और जलवायु संबंधी महत्त्व की दृष्टि से भी देखने और मूल्यांकन करने की जरूरत है। अगर अरावली की पहाड़ियों में अवैध और अवैज्ञानिक तरीके से खनन पर रोक नहीं लगाई गई, तो निश्चित रूप से निकट भविष्य में इसके गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं।

एआई सुपरपावर बनने का सपना, मगर शिक्षा में पुरानी सोच क्यों? क्या इनोवेशन की दौड़ में पीछे रह गया भारत

भारत में बदलाव और विकास को रफ्तार देने के लिए नवाचार एक अहम पहलू है। इस समय कृत्रिम मेधा के माध्यम से भारत सबसे अग्रणी होने का प्रयास कर रहा है। इंटरनेट की शक्ति को 6जी से आगे ले जाने की कोशिश हो रही है और हर पुराने तरीके को कृत्रिम मेधा की सहायता से बदलने की पहल हो रही है। दावा किया जाता है कि वैश्विक स्तर पर विज्ञान और नवाचार के मामले में भारत तेजी से उभर रहा है। शोध कार्यों में भी देश किसी से पीछे नहीं है। पेटेंट की बात की जाए तो इसके लिए उद्यम और प्रौद्योगिकी में हम लगातार नए अन्वेषण कर रहे हैं। पेटेंट मामले में भारत दुनिया में छठे स्थान पर पहुंच गया है। विज्ञान और इंजीनियरिंग के मामले में दावा किया जाता है कि हम शीर्ष देशों की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। मगर शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार की राह अब भी कई तरह की चुनौतियों से घिरी हुई है।

वैश्विक नवाचार में जो मुकाबला होता है, उसमें भारत ने लगातार अपनी बढ़त बनाई है और वह 90वें पायदान से तीसवें स्थान पर पहुंच गया है। भारत के भावी प्रौद्योगिकी मिशनों में भी इसका विस्तार करने और सार्वजनिक क्षेत्र में कृत्रिम मेधा के विकास का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन इसके लिए शिक्षा में जो परिवर्तन होना चाहिए, वह अभी तक नहीं हुआ है। शिक्षा परिसरों में जो नवाचार दिखाई देना चाहिए, वह भी नहीं दिखाई देता। निजी क्षेत्र ने विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थानों में भारी निवेश किया है। पंजाब को ही लें। इस राज्य में तीन मुख्य विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और दूसरे विश्वविद्यालय जरूर खुल गए हैं, लेकिन उनमें विद्यार्थियों की कमी तो है ही, वहीं सटीक पाठ्यक्रमों का अभाव भी नजर आता है। यहां कहीं नवाचार नहीं दिखाई देता है।

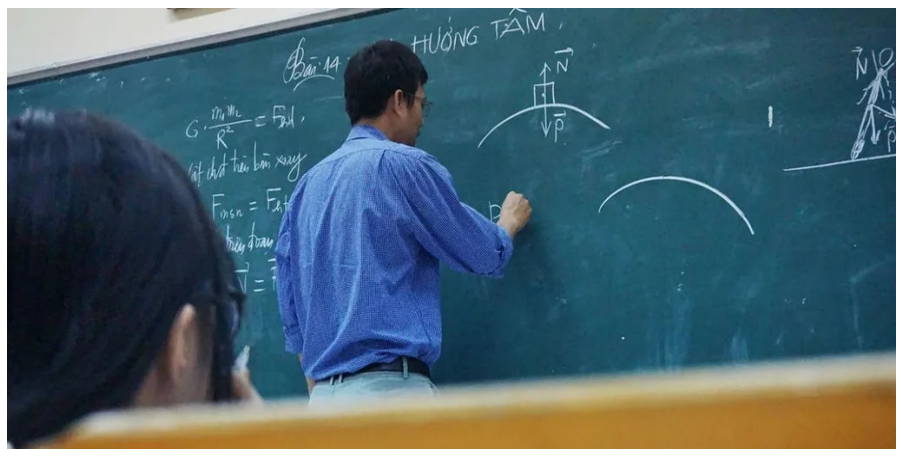

केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया था। इसमें देश की विभिन्न शिक्षा प्रणालियों को एक साथ मिला कर सीधा रास्ता निकालने की कोशिश की गई थी। अब इस अभियान में भी नवाचार की घोषणा शिक्षा मंत्री ने की है। शिक्षा क्षेत्र में बड़े सपने देखने के साथ भारत अब अंतरिक्ष विज्ञान में भी नई बुलंदियों को छूना चाहता है। वह अमेरिका या रूस के मुकाबले किसी भी तरह पीछे नहीं रहना चाहता। हालांकि दूसरे क्षेत्रों में विकास की अब भी बहुत गुंजाइश है। वैसे मुद्दे की बात यह है कि शिक्षा के सभी पुराने ढर्रे अब बदले जाने चाहिए।

विज्ञान की समझ हर विद्यार्थी में हो, तभी शिक्षा में विकास के सपने पूरे हो सकेंगे। मगर इन सबके लिए पूंजी चाहिए। नीति आयोग यह कहता है कि कम से कम छह फीसद व्यय शिक्षा के विकास पर होना चाहिए, लेकिन आजादी के इतने वर्षों बाद और विकास की बुलंदियों को छू लेने के दावों के बावजूद देश ने कभी भी सकल घरेलू उत्पाद में से छह फीसद शिक्षा पर खर्च नहीं किया। हमेशा यह खर्च आंकड़ों में दिखाया जाता है, फीसद में नहीं, ताकि आबादी के लिहाज से तेजी से बढ़ते हुए देश में शिक्षा में बदलाव की धीमी गति को लेकर कोई उलझन पैदा न हो।

हम शिक्षा के विकास में कृत्रिम मेधा के जरिए विश्व का नेतृत्व करना चाहते हैं। सरकार का कहना है कि कृत्रिम बुद्धिमता नैतिक, पारदर्शी और डेटा गोपनीयता सिद्धांतों पर आधारित हो। इसके अलावा यह समावेशी और मितव्ययी हो, लेकिन सच तो यह है कि मितव्यय के नाम पर धन का आबंटन अब भी कम है, लेकिन न तो यह समावेशी हो सका है और न ही वहनीय। सवाल यह है कि अगर समावेशी, रोजगारपरक और अन्वेषणपूर्ण शिक्षा को गांव-गांव तक पहुंचाना है, तो इसके लिए उद्यम कहां है?

अगर आज भी यह रपट आती है कि भारत में हजारों प्राथमिक विद्यालयों में एक-एक अध्यापक कई कक्षाओं को संभाल रहे हैं, तो शिक्षा में नई तकनीक और वैज्ञानिक दृष्टि को आत्मसात करने का लक्ष्य कब पूरा होगा? पंजाब को ही लें, आज भी यहां अधिकतर छात्र कला संकायों की ओर जा रहे हैं। जबकि नई शिक्षा नीति यह कहती है कि शुरू से लेकर उच्च स्तर तक नई पीढ़ी कला और साहित्य के साथ-साथ विज्ञान एवं तकनीक का भी अध्ययन करे।

दूसरी ओर आलम यह है कि स्कूलों में दाखिले का फीसद जरूर बढ़ गया है, लेकिन दसवीं तक आते-आते विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ रही है। इसकी वजह है-परिवारों की आर्थिक असुरक्षा और रोजगार की अनिश्चितता। वहीं देश की युवा पीढ़ी में काम करने की इच्छा लगातार घट रही है, तो इसका कारण उदारता से बांटी गई रेवड़ियां भी हैं।

अजब विडंबना है कि एक ओर देश आर्थिक शक्ति बनता दिख रहा है और हम भविष्य में तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने का दावा कर रहे हैं। आजादी के शतकीय महोत्सव 2047 तक हम महाशक्ति बनना चाहते हैं। दूसरी ओर युवा पीढ़ी को अनुकंपा के जरिए धीरज रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसे विरोधाभास नहीं तो और क्या कहा जा सकता है।

उच्च शिक्षा में ज्यादातर विद्यार्थी कला और साहित्य क्षेत्र में शोध करना चाहते हैं। विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में शोध की प्रवृत्ति नहीं बढ़ रही। हम कृत्रिम मेधा से नवाचार की ओर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमारा शोध इस क्षेत्र की बुलंदियों की ओर जाता नहीं दिख रहा। हम कृत्रिम मेधा से नवाचार की बात जरूर करते हैं, लेकिन सवाल है कि कितने प्रशिक्षण संस्थान हमने इसके लिए बनाए हैं। कितने अध्यापकों को हमने नई शिक्षा विधि में निपुण बनाया है?

नई शिक्षा नीति तो कहती है कि युवा पीढ़ी के प्रशिक्षण को किताबों के साथ-साथ यथार्थ से भी जोड़ा जाना चाहिए, मगर वास्तव में ऐसा हो नहीं पा रहा है। पुरानी नौकरियां अब खत्म हो रही हैं, क्योंकि दफ्तरों में सब काम कागज रहित होता जा रहा है। हालांकि अब भी अधिकतर संस्थानों में नौकरियों का वही पुराना ढर्रा है। दूसरी ओर चिकित्सा और इंजीनियरिंग की डिग्रियां अब युवा पीढ़ी के लिए अंतिम विकल्प नहीं रह गई हैं। इसमें दोराय नहीं कि अब कृत्रिम मेधा में दक्ष पीढ़ी तैयार हो रही है। यही लक्ष्य भी होना चाहिए। मगर अभी तक इसमें नवाचार सतही स्तर पर ही दिखाई देता है। पाठ्यक्रमों में बदलाव नहीं दिख रहा और न ही इस दिशा में पुस्तकें लिखी जा रही हैं। अध्यापन विधि भी नहीं बदल रही।

जबकि यथार्थ के धरातल पर नई पीढ़ी को खड़ा करना नई शिक्षा नीति का लक्ष्य होना चाहिए। फिलहाल इस बारे में दावे तो किए जाते हैं, लेकिन यह वास्तविक रूप से कहीं गतिमान नजर नहीं आता। अगर निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित कर समावेशी विकास के लिए दरवाजे खोलने हैं, तो समावेशी शिक्षण होना चाहिए। इस पर अभी बहुत काम करने की जरूरत है।

कृत्रिम मेधा के उपयोग में आगे बढ़ने के दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन हमारी उत्पादन प्रक्रिया में इसके इस्तेमाल से लागत कम होती नजर नहीं आती। कृषि क्षेत्र में तो आज भी कृत्रिम मेधा का इस्तेमाल न के बराबर है। समग्र शिक्षा अभियान में नवाचार का सपना सुंदर है, परंतु देश इस दिशा में तेजी से बढ़ता हुआ नजर नहीं आता। ऐसे में शिक्षा को नवाचार से जोड़ने के प्रयास करने होंगे।

सब कुछ शेयर करने की बीमारी और खोती हुई प्राइवेसी हम खुद को क्यों बेच रहे हैं? कितना सुरक्षित है अपना जीवन?

सूचना के इस असीमित एवं अनियंत्रित प्रवाह के दौर में हम सब सार्वजनिक प्रदर्शन को आतुर हैं। अनावश्यक रूप से हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम कहां घूम रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, हमारी जीवनशैली कितनी चमक-दमक से भरी है। मसलन, कुछ विषय, जिन्हें दो दशक पहले तक निजी माना जाता था, हम अब सोशल मीडिया पर उन्हें भी सरेआम प्रदर्शित कर रहे हैं। सोशल मीडिया के शुरुआती दिनों में यह ठीक लगा, पर समय के साथ ऐसा महसूस होने लगा है कि हम कहीं तो चूक रहे हैं! डिजिटल विकास मानव सभ्यता की एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है, पर इसी विकास ने एक ऐसी चुनौती भी सामने रख दी है, जिसकी गंभीरता को हम अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। निजता की निरंतर कमी अभी के समय की सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है।

बीते वर्षों में तकनीक ने हमारी दुनिया को भले ही छोटा और सुविधाजनक बनाया हो, पर इसके साथ उसने मनुष्य को इतना सार्वजनिक भी कर दिया है कि उसके निजी जीवन की सीमाएं लगभग धूमिल हो चली हैं। सरल शब्दों में कहें तो आज के समय में हमने अपने शयन-कक्ष में सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है और इसकी पहुंच पूरी दुनिया को दे रखी है। असली समस्या यह है कि अपनी इस प्रवृत्ति से हम खुश हैं!

यह विडंबना ही है कि जिस दौर में सूचना सबसे सुलभ है, उसी दौर में मनुष्य अपने बारे में उपलब्ध सूचनाओं पर सबसे कम नियंत्रण रख पा रहा है। यह भी स्पष्ट होता जा रहा है कि आने वाले वर्षों में निजता वही लोग सुरक्षित रख पाएंगे, जिनके पास तकनीकी अनुशासन, जागरूकता और संसाधन होंगे। आज का नागरिक अपने जीवन के अनेक हिस्सों, तस्वीरों, यात्राओं, निजी क्षणों, संबंध, विचार और भावनाओं को जाने-अनजाने में सार्वजनिक कर रहा है और इसे हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मान रहे हैं।

सोशल मीडिया मंच यह भ्रम पैदा करते हैं कि वे इंसान को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देते हैं, पर वास्तविकता यह है कि वे मनुष्य को निरंतर एक ऐसे सार्वजनिक मंच पर ले आते हैं, जहां वह अपनी निजता खुद क्षीण करता चलता है। निजी और सार्वजनिक के बीच की रेखा लगभग समाप्त हो चुकी है। घर की दीवारें अब सुरक्षा का आश्वासन नहीं देतीं। हम अपने ही हाथों अपनी गतिविधियों को दर्ज करते जाते हैं, और एक बार दर्ज हुई जानकारी हमारी इच्छानुसार मिट नहीं पाती।

क्या हमने सुविधा की तलाश में अपनी सुरक्षा गिरवी रख दी है? एक समय था जब बाजार वस्तुओं पर चलता था। अब बाजार डेटा पर चलता है। यह डेटा हम स्वयं उपलब्ध कराते हैं, और यही डेटा हमारी पहचान, पसंद, आदतों और हमारे व्यवहार का मानचित्र तैयार करता है। इस मानचित्र से कंपनियां अनुमान लगाती हैं कि हम क्या सोचते हैं, क्या खरीदते हैं, किसे पसंद करते हैं और किस बात से प्रभावित होते हैं। यह अनुमान कभी-कभी इतना सटीक होता है कि मनुष्य के खुद को पढ़ने से पहले उसे मशीन पढ़ लेती है। सोशल मीडिया मंच हमें मुफ्त लगते हैं, पर इस मुफ्त के पीछे हमारी निजता का गंभीर मूल्य छिपा है।

आने वाले कुछ ही समय में निजता समाज में वर्ग-भेद का आधार बन जाएगी। भविष्य में समाज का एक छोटा वर्ग वह होगा, जिसकी सार्वजनिक उपस्थिति न्यूनतम होगी। उसके बारे में इंटरनेट पर बहुत कम जानकारी उपलब्ध होगी। यह वर्ग न केवल अधिक सुरक्षित होगा, बल्कि एक प्रकार के 'एलीट' समूह के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि उसके पास निजता नाम की दुर्लभ निधि होगी। इसके उलट समाज का एक बड़ा हिस्सा वह होगा, जिसकी डिजिटल उपस्थिति अत्यधिक होगी, जिसका जीवन खुली किताब की तरह इंटरनेट पर दर्ज होगा और समाज का यह हिस्सा पिछड़ा हुआ माना जाएगा। निजता ही आने वाले समय का नया 'स्टेटस सिंबल' या हैसियत का प्रतीक बन सकती है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआइ, चेहरे से पहचान करने वाली मशीन यानी फेस-रिकग्निशन, डीपफेक जैसे उपकरण जिस गति से विकसित हो रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि भविष्य में निजता की समस्या और जटिल होगी। अब किसी व्यक्ति की आवाज, तस्वीर या वीडियो का दुरुपयोग करना पहले से कहीं अधिक आसान हो चुका है। ऐसे माहौल में जो व्यक्ति अपनी जानकारी कम साझा करेगा, वही अधिक सुरक्षित रहेगा। सुरक्षा अब दीवारों या तिजोरियों से नहीं, बल्कि सूचनात्मक संयम से आएगी।

निजता का महत्त्व केवल किसी बात को छिपाने में नहीं है। यह मनुष्य के निर्णयों, उसके मनोविज्ञान और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा का मूल सूत्र है। जब किसी व्यक्ति के बारे में कम जानकारी उपलब्ध होती है, तभी उसके पास अपनी पहचान पर नियंत्रण होता है। निजता उसे वह स्थान देती है, जहां वह बिना दबाव, बिना भय और बिना निगरानी के सोच सकता है।

निजता की सुरक्षा की दिशा में हम अभी से कुछ बुनियादी कदम उठा सकते हैं जैसे सोशल मीडिया पर कम व्यक्तिगत जानकारी साझा करना, अपनी जगह को साझा करने को सीमित रखना, अलग-अलग एप को दी गई अनुमतियों की समीक्षा करना, पासवर्ड सुरक्षा मजबूत करना, अनावश्यक डिजिटल गतिविधियों से दूरी बनाना। निजता की रक्षा एक दिन का काम नहीं, बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया है। सूचना-युग में मनुष्य जितना अधिक सार्वजनिक हुआ है, उतना ही अधिक असुरक्षित भी। भविष्य का समाज वही व्यक्ति मजबूत और स्वतंत्र मानेगा, जिसकी व्यक्तिगत जानकारी उसके ही नियंत्रण में होगी। निजता अब केवल एक निजी विषय न रहकर सामाजिक, नैतिक और लोकतांत्रिक प्रश्न बनती जा रही है। इसलिए जरूरी है कि हम आज से ही अपनी निजता को संचित करना शुरू करें, क्योंकि जो बातें हम सहजता से साझा करते हैं, वही भविष्य में सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती हैं।

बंगाल में लोकतंत्र, विकास और अस्मिता की निर्णायक परीक्षा-घड़ी

पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय एक ऐसे संक्रमण काल से गुजर रही है, जहां सत्ता, संघर्ष, कानून और जनभावना-चारों धाराएं एक-दूसरे से टकराती हुई दिखाई देती हैं। यह टकराव केवल भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई भर नहीं है, बल्कि यह उस शासन शैली, लोकतांत्रिक मर्यादा और विकास दृष्टि की भी परीक्षा है, जिसके आधार पर बंगाल अपनी आने वाली राजनीतिक दिशा तय करेगा। लंबे समय तक 'खेला होगा' के नारे के सहारे भाजपा को रोकने में सफल रहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने इस बार परिस्थितियां अपेक्षाकृत अधिक जटिल, चुनौतीपूर्ण और बहुआयामी नजर आ रही हैं। आज समूचे देश की नजरे पश्चिम बंगाल पर टिकी है। वहां आगामी विधानसभा काफी रोमांचक एवं निर्णायक होगा, जिसमें पश्चिम बंगाल का नया भविष्य बुनने की दिशाएं उद्घाटित होगी।

एक ओर केंद्र और राज्य के बीच टकराव अपने चरम पर है, तो दूसरी ओर केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई, अदालती टिप्पणियां और कानूनी बहसें राजनीतिक विमर्श को नियंत्रित कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणियों ने केवल एक कानूनी प्रश्न ही नहीं उठाया, बल्कि यह संकेत भी दिया कि राज्य सरकारों द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसियों के कामकाज में हस्तक्षेप की सीमाएं कहां तक हो सकती हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने ममता बनर्जी की उस राजनीतिक छवि को आंशिक रूप से प्रभावित किया है, जो अब तक स्वयं को केंद्र के कथित दमन के विरुद्ध संघीय ढांचे की रक्षक के रूप में प्रस्तुत करती रही हैं। अदालतों में लंबी चलने वाली कानूनी लड़ाइयों का राजनीतिक प्रभाव तुरंत और गहरा होता है, विशेषकर तब, जब चुनाव नजदीक हों और जनता का ध्यान प्रशासनिक उपलब्धियों से हटकर आरोप-प्रत्यारोप पर केंद्रित होने लगे। बंगाल की राजनीति की एक विशिष्ट विशेषता यह रही है कि यहां विचारधारा और भावनाएं अत्यंत तीव्र रूप से अभिव्यक्त होती हैं। वाम मोर्चे के लंबे शासन के बाद ममता बनर्जी का उदय एक जनांदोलन के रूप में हुआ था। उन्होंने न केवल वामपंथी वर्चस्व को तोड़ा, बल्कि खुद को गरीब, हाशिए के वर्ग और क्षेत्रीय अस्मिता की आवाज के रूप में स्थापित किया। शुरुआती वर्षों में उनकी सरकार ने कुछ कल्याणकारी योजनाओं और सशक्त राजनीतिक संप्रेषण के माध्यम से जनता का विश्वास भी अर्जित किया। किंतु समय के साथ सत्ता का केंद्रीकरण, संगठन पर अत्यधिक नियंत्रण और विरोध के प्रति असहिष्णुता जैसे आरोप भी समानांतर रूप से उभरते गए।

भाजपा ने इन्हीं कमजोरियों को अपना राजनीतिक आधार बनाने की कोशिश की है। 2019 के लोकसभा चुनावों से लेकर अब तक भाजपा ने बंगाल में अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत किया है और हिंदुत्व, राष्ट्रवाद तथा भ्रष्टाचार विरोधी विमर्श को आक्रामक रूप से आगे बढ़ाया है। हालांकि विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने भारी बहुमत से वापसी की, लेकिन यह भी सच है कि भाजपा बंगाल की राजनीति में एक स्थायी और निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुकी है। मत प्रतिशत में अंतर और सीटों का आंकड़ा भाजपा के लिए भले ही निराशाजनक रहा हो, पर संगठनात्मक विस्तार और सामाजिक आधार का विस्तार उसके लिए भविष्य की संभावनाओं के द्वार खोलता है। हाल के वर्षों में बंगाल में विकास का प्रश्न अपेक्षाकृत पीछे छूटता दिखाई दिया है। उद्योग, निवेश और रोजगार के मुद्दे राजनीतिक शोर में दब गए हैं। आम जनता की एक बड़ी चिंता यह भी है कि राज्य की राजनीति निरंतर टकराव और हिंसा के आरोपों से क्यों घिरी रहती है। चुनावी हिंसा, राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर हमले और प्रशासन की निष्पक्षता पर उठते सवाल राज्य की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। पड़ोसी देशों से अवैध घुसपैठ, सीमावर्ती इलाकों में जनसांख्यिकीय बदलाव और कानून-व्यवस्था की चुनौतियां भी राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन चुकी हैं। इन मुद्दों पर ममता सरकार का रुख अक्सर रक्षात्मक दिखाई देता है, जबकि भाजपा इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा और सांस्कृतिक पहचान से जोड़कर व्यापक समर्थन जुटाने का प्रयास करती है।

महाराष्ट्र के शहरी निकाय चुनावों और बिहार में भाजपा को मिली हालिया सफलता ने पार्टी के आत्मविश्वास को निश्चित रूप से बढ़ाया है। भाजपा का यह विश्वास कि बंगाल अब भी राजनीतिक परिवर्तन के लिए तैयार है, केवल चुनावी आंकड़ों पर आधारित नहीं है, बल्कि वह इसे एक लंबी रणनीति का हिस्सा मानती है। किंतु बंगाल कोई साधारण राजनीतिक मैदान नहीं है। यहां की सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक चेतना और ऐतिहासिक स्मृति किसी भी दल के लिए आसान नहीं रही है। ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत आज भी उनकी जमीनी पकड़ और भावनात्मक अपील है, जो उन्हें भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से अलग, एक क्षेत्रीय और स्थानीय नेता के रूप में स्थापित करती है। आने वाले विधानसभा चुनाव वास्तव में इस बात की कसौटी होंगे कि जनता विकास, स्थिरता और कानून-व्यवस्था को प्राथमिकता देती है या फिर भावनात्मक और पहचान आधारित राजनीति को? क्या ममता बनर्जी लगातार चौथी बार सत्ता में लौटकर यह सिद्ध कर पाएंगी कि केंद्र से टकराव ही उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी है, या भाजपा जनता को यह विश्वास दिलाने में सफल होगी कि परिवर्तन ही स्थायित्व और विकास का रास्ता है, यह प्रश्न अभी खुला हुआ है। अदालती प्रक्रियाएं, राजनीतिक बयानबाजी और चुनावी रणनीतियां अपनी जगह हैं, लेकिन अंतिम निर्णय बंगाल की जनता के हाथ में है।

पश्चिम बंगाल की राजनीति आज संकीर्णता और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के ऐसे दौर से गुजर रही है, जिसने विकास की गति को गंभीर रूप से अवरुद्ध किया है। कभी देश की आर्थिक, औद्योगिक और बौद्धिक राजधानी कहलाने वाला बंगाल-विशेषकर कोलकाता, आज निवेश, उद्योग और रोजगार के मोर्चे पर पिछड़ता हुआ दिखाई देता है। ममता बनर्जी के लंबे शासनकाल में औद्योगिक विश्वास का क्षरण, पूंजी पलायन, बंद होती इकाइयाँ और युवाओं का अन्य राज्यों की ओर पलायन इस गिरावट के स्पष्ट संकेत हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वायत्तता पर उठते प्रश्न, विपक्षी आवाज़ों का दमन और चुनावी हिंसा की घटनाएँ राज्य के लोकतांत्रिक स्वास्थ्य पर गहरी चोट करती हैं। इसके साथ ही, राज्य में सामाजिक ताने-बाने को लेकर बढ़ती आशंकाएँ भी कम चिंताजनक नहीं हैं। अनेक क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था, धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक संबंधों को लेकर शिकायतें सामने आती रही हैं; विशेषकर हिंदू समाज के एक हिस्से में असुरक्षा की भावना ने जनमन को आहत किया है। इन घटनाओं और धारणाओं ने जनता के भरोसे को कमजोर किया है और शासन के प्रति निराशा को बढ़ाया है। राजनीति जब पहचान और विभाजन के इर्द-गिर्द सिमटती है, तो विकास, समावेशन और सामाजिक सौहार्द पीछे छूट जाते हैं, यही आज के बंगाल की त्रासदी बनती दिख रही है।

ऐसे समय में बंगाल की जनता के लिए अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति सजग होना अनिवार्य है। यह राज्य केवल भौगोलिक इकाई नहीं, बल्कि उसकी अस्मिता उसकी बौद्धिक परंपरा, भावनात्मक संवेदनशीलता, धार्मिक सहअस्तित्व, आध्यात्मिक खोज और समृद्ध साहित्यिक विरासत से निर्मित है-रवींद्रनाथ से विवेकानंद तक की धरोहर इसे दिशा देती रही है। दंगों, हिंसा और भय के साए में इस अस्मिता पर जो दाग लगे हैं, उन्हें मिटाने का मार्ग शांतिपूर्ण, जागरूक और निर्भीक लोकतांत्रिक सहभागिता से ही निकलेगा। आगामी चुनाव जनता के लिए आत्ममंथन और आत्मनिर्णय का अवसर हैं-जहाँ मत केवल सत्ता नहीं, बल्कि बंगाल के भविष्य, उसकी संस्कृति और उसके लोकतांत्रिक आत्मसम्मान की रक्षा का माध्यम बनना चाहिए। बंगाल की बनती नई तस्वीर अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। यह तस्वीर संघर्ष और संभावनाओं, आशंकाओं और उम्मीदों से बनी है। एक ओर सत्ता का अनुभव और जनाधार है, तो दूसरी ओर आक्रामक विपक्ष और राष्ट्रीय राजनीति की ताकत। लोकतंत्र की यही खूबी है कि वह अंतिम शब्द जनता को देता है। बंगाल के मतदाता ही तय करेंगे कि शह-मात की इस राजनीति में अगली चाल किसकी होगी और कौन-सा पक्ष अंततः बाजी मारेगा।

महिलाओं के लिए बजट की समझ बढ़ाएगा 'मिलेनियम मैम्स' का विशेष बजट विश्लेषण सत्र

नई दिल्ली। महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में अग्रणी संस्था मिलेनियमन मेम द्वारा आगामी केंद्रीय बजट को महिलाओं के लिए सरल और उपयोगी रूप में समझाने हेतु एक विशेष ङबजट विश्लेषण सत्रङ का आयोजन किया जा रहा है। इस संस्था का नेतृत्व कर रहीं विष्णू धानुका वर्षों से महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से जागरूक बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं।

इस सत्र का उद्देश्य केंद्रीय बजट जैसे जटिल विषय को आसान भाषा में प्रस्तुत करना है, ताकि महिलाएं यह समझ सकें कि बजट का सीधा असर उनके परिवार, घरेलू अर्थव्यवस्था, आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं से जुड़ी सरकारी योजनाओं पर किस प्रकार पड़ता है। कार्यक्रम के दौरान बजट से संबंधित प्रमुख प्रावधानों को सरल उदाहरणों के माध्यम से समझाया जाएगा, जिससे पहली बार सीखने वाली महिलाएं भी इसे आसानी से आत्मसात कर सकें। यह पहल समाज में हो रहे सकारात्मक बदलाव को भी दर्शाती है, जहां महिलाएं अब केवल घर-गृहस्थी तक सीमित न रहकर शिक्षा, नीति और आर्थिक विषयों में सक्रिय भागीदारी कर रही हैं।

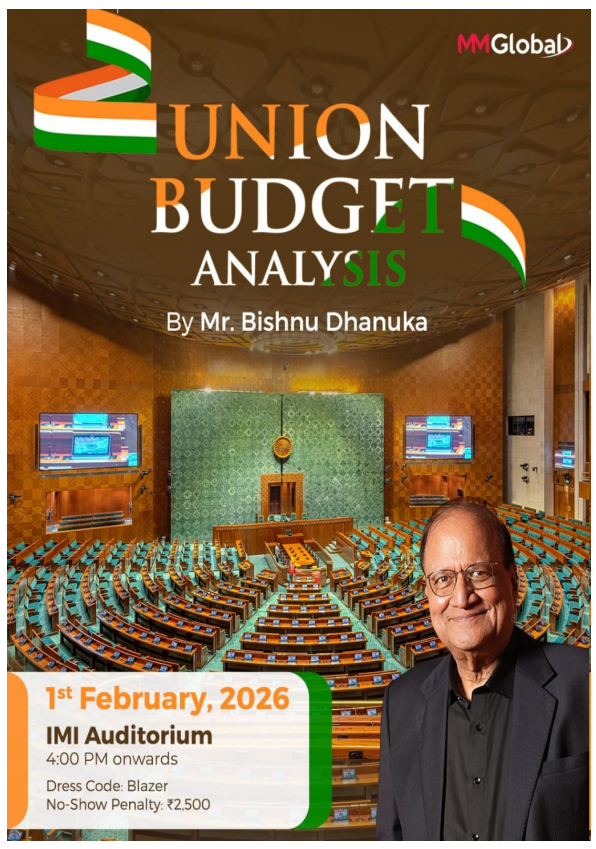

मिलेनियम मैम्स का यह प्रयास महिलाओं को ज्ञान के माध्यम से सशक्त बनाते हुए उन्हें देश की आर्थिक दिशा को समझने और उस पर विचार रखने का आत्मविश्वास प्रदान करता है। उल्लेखनीय है कि बिश्नु धनुका के मार्गदर्शन में यह बजट विश्लेषण कार्यक्रम हर वर्ष आयोजित किया जाता है, जिसमें बजट को बेहद सरल और व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

मीडिया संस्थानों से आग्रह है कि वे इस महत्वपूर्ण और प्रेरणादायी पहल का कवरेज करें, जो एक पूर्णतः महिला संगठन द्वारा वित्तीय जागरूकता और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में किया जा रहा एक उल्लेखनीय प्रयास है।

अनाधिकृत रूप से भू-विन्यास (लेआउट) विकसित करने के विरूद्ध की गई ध्वस्तीकरण की कार्यवाही

बीडा प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत कराये कोई भी निर्माण न करें-मुख्य कार्यपालक अधिकारी

किसी भू-विन्यास (लेआउट) में कोई भी भूखण्ड क्रय करने से पूर्व मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में बीडा से प्राप्त कर लें जानकारी

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। जिलाधिकारी/मुख्य कार्यपालक अधिकारी बीड़ा शैलेष कुमार के कुशल मार्गदर्शन में उप कार्यपालक अधिकारी अनीता देवी द्वारा अवगत कराया गया कि बीडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र मौजा हरियांव तहसील व जिला भदोही के गाटा सं0 62, 63मि0, 68 पर लगभग 7800 वर्गमी0 में देवी प्रसाद पुत्र विश्वनाथ, निवासी-हरियांव, भदोही, श्रीमती शालू देवी पत्नी स्व0 बच्चा लाल, निवासी चकइनायत, भदोही व कार्तिक जायसवाल पुत्र देवी प्रसाद निवासी चकइनायत, भदोही हालमुकाम काजीसराय, पो0 बड़गांव, हरहुआ, तह0-सदर, जिला वाराणसी द्वारा अनाधिकृत रूप से भू-विन्यास (लेआउट) विकसित किया गया था।

बीडा द्वारा उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत अनधिकृत निर्माणकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस व विकास कार्य रोकने का आदेश निर्गत करते हुए सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया, परन्तु अनधिकृत निर्माणकर्ताओं ने उक्त लेआउट को प्राधिकरण से स्वीकृत नहीं कराया गया। अतः 22 जनवरी 2026 को जिलाधिकारी, भदोही/मुख्य कार्यपालक अधिकारी बीडा के आदेश के क्रम में नामित मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी (न्यायिक), भदोही बरखा सिंह के

नेतृत्व में उक्त अवैध निर्माण के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही प्राधिकरण के अधिकारी / कर्मचारियों द्वारा प्रशासन के सहयोग से सम्पन्न करायी गयी। जिलाधिकारी/मुख्य कार्यपालक अधिकारी बीडा द्वारा इस सम्बन्ध में जनसामान्य से यह अपेक्षा की गयी है कि बीडा प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत कराये कोई भी निर्माण न करें तथा किसी भू-विन्यास (लेआउट) में कोई भी भूखण्ड क्रय करने से पूर्व लेआउट मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में प्राधिकरण से जानकारी प्राप्त कर लें। जिन व्यक्तियों ने बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण कर लिया है, उक्त अवैध निर्माण को भी शीघ्र ही प्राधिकरण से विनियमित करायें। अवैध निर्माण के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया अनवरत् जारी रहेगी।

श्रम विभाग द्वारा श्रमिक पंजीकरण नवीनीकरण योजनाओं के हीतलाभ कैंप का आयोजन

भदोही। जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी के निर्देश पूर्व माध्यमिक विद्यालय मसूदी अभोली दुर्गागंज जनपद भदोही में श्रमिक पंजीकरण, नवीनीकरण, योजनाओं के हितलाभ, एवं प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन पेंशन योजना के अंतर्गत कैंप का आयोजन किया गया।

कैंप में मुख्य अतिथि मनोज शर्मा श्रम प्रवर्तन अधिकारी भदोही रहे इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित निर्माण श्रमिकों से मात्र ?20 देकर अधिक से अधिक श्रमिक पंजीयन करने का आह्वान किया गया तथा लोगों को जागरूक रहने की भी अपील की गई जिससे वह समय से हित लाभ की योजनाओं का समय-समय पर आवेदन कर योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। तथा प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन करा कर अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं

इसी क्रम में अजय यादव जिला समन्वयक मानव संसाधन एवं महिला विकास संस्थान वाराणसी द्वारा बताया गया कि ये सभी अतिगरीब बनवासी परिवार से हैं जो विभिन्न निर्माण क्षेत्र में कार्य करते हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं उन्होंने बताया कि इस कैंप में कई ग्राम सभाओं के बनवासी परिवार के लोग उपस्थित हैं । ऐसे परिवारों का सहयोग करने के लिए मेरी संस्था सदैव समर्पित है। इस अवसर पर ग्राम सभा मसूदी के ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि विध्यवासिनी पांडे, वीरेंद्र प्रसाद यादव रामविलास बिंद दीपक मौर्य, संस्था की तरफ से राजमणि, नरेंद्र, शिव कुमारी, कमलेश, विकास, अंबिका प्रसाद, वीरेंद्र , शेषमणि तथा सीएसी से आए राहुल कुमार सहित काफी संख्या में संस्था के पदाधिकारी , कार्यकर्ता, एवं निर्माण श्रमिक उपस्थित रहे। कैंप में 1 42 बनवासी परिवार उपस्थित हुए लगभग 30 महिला/ पुरुष श्रमिकों का पंजीकरण एवं 35 नवीनीकरण किया गया।

कौशांबी में मवेशी से टकराई तेज रफ्तार बोलेरो 7 लोग घायल, एयरबैग खुलने से बची जान

मंत्र भारत संवाददाता

कौशाम्बी। जनपद के कोखराज थाना क्षेत्र में देर रात एक तेज रफ्तार कार आवारा पशु से टकराकर पलट गई इस दुर्घटना में कार सवार सात लोग घायल हो गए हालांकि, कार के एयरबैग खुलने से सभी यात्रियों की जान बच गई। यह घटना कोखराज गांव के समीप हुई। कार, कानपुर से बनारस की ओर जा रही थी तभी अचानक एक आवारा पशु सामने आ गया, टक्कर के बाद कार कई बार पलटी और सड़क किनारे जा गिरी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर और घायलों को एंबुलेंस से नज़दीकी अस्पताल में पहुंचाया कार चालक वीर सिंह (45) जो कानपुर के निवासी हैं बताया कि वह सात लोगों को लेकर बनारस जा रहे थे। घायलों में प्रशांत सचान (30), चालक वीर सिंह और एक महिला शामिल हैं। प्रशांत सचान और वीर सिंह को प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई महिला का हाथ टूटने के कारण उसे प्रयागराज के एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कार में सवार अन्य यात्री पूरी तरह सुरक्षित है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार को हाईवे से हटाकर थाने में खड़ा कर दिया है।

जनता दर्शन में जिलाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अधिकारियों को जोड़कर कराया त्वरित निस्तारण

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी शैलेष कुमार ने जनपद के विभिन्न ग्रामीण अंचलों से आए फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को जोड़कर शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए।

जनसुनवाई के दौरान जिलाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबंधित अधिकारियों को मौके से ही जोड़ते हुए शिकायतों का तत्काल, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित कराया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक प्रकरण का समयबद्ध निस्तारण किया जाए, जिससे आम जनता को शीघ्र राहत मिल सके। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप जनता की समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी एवं संवेदनशील समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विशेष रूप से बुजुर्गों, महिलाओं और कमजोर वर्गों से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता दर्शन में प्राप्त प्रत्येक शिकायत का स्थलीय सत्यापन कर समय सीमा के भीतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, ताकि फरियादियों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने कहा कि जनता दर्शन शासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का प्रभावी माध्यम है, जिसके माध्यम से नागरिकों की समस्याओं का समाधान कर प्रशासन के प्रति विश्वास को और अधिक मजबूत किया जा सकता है।

माघ मेला प्रयागराज में श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय-2 का गूढ़ विवेचन

कृष्णार्पित ट्रस्ट के पंडाल में कर्म, ज्ञान और ब्राह्मी स्थिति का दिव्य संदेश

प्रयागराज, माघ मेला। माघ मेला क्षेत्र के हर्षवर्धन मार्ग स्थित कृष्णार्पित ट्रस्ट के पंडाल में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के द्वितीय दिवस पर श्रीमद्भगवद्गीता के द्वितीय अध्याय (सांख्य योग) का अत्यंत गंभीर, तात्त्विक और जीवन-दर्शन से परिपूर्ण विवेचन प्रस्तुत किया गया। कथा वाचन इं. देवेंद्र नाथ शुक्ला 'कृष्णार्पित' द्वारा किया गया।

उल्लेखनीय है कि प्रथम दिवस पर भी कथा वाचन इं. देवेंद्र नाथ शुक्ला 'कृष्णार्पित' द्वारा ही किया गया था, जिसमें भारतीय संस्कृति के चार स्तंभ–गंगा, गाय, गायत्री और गीता–पर विस्तृत प्रकाश डाला गया था।

कार्यक्रम का शुभारंभ द्वितीय दिवस पर वैदिक मंत्रोच्चार एवं 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः' के सामूहिक उच्चारण के साथ हुआ। शरणागत शिष्य अर्जुन से गीता का उपदेश कथावाचक ने बताया कि गीता का द्वितीय अध्याय शरणागति का अध्याय है। अर्जुन जब शोक, करुणा और मोह से व्याकुल होकर शस्त्र त्याग देता है, तब वह श्रीकृष्ण की शरण में आता है और स्वयं को शिष्य घोषित करता है। यहीं से भगवद्गीता का वास्तविक उपदेश आरंभ होता है। अर्जुन की मानसिक स्थिति को श्लोक के माध्यम से समझाया गया– 'गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः?' अर्थात अर्जुन के हाथ से गाण्डीव गिर रहा है, शरीर जल रहा है और मन भ्रमित हो गया है। नश्वर देह और अमर आत्मा का सिद्धांत कथा में श्रीकृष्ण द्वारा प्रतिपादित आत्मा की अमरता को केंद्र में रखते हुए कहा गया कि– देह नश्वर है, परिवर्तनशील है, परंतु आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। श्लोकों के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया कि जन्म-मरण केवल

शरीर का होता है, आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है। क्षत्रिय धर्म और कर्तव्य बोध कथावाचक ने कहा कि अर्जुन का युद्ध से विमुख होना कर्तव्य से पलायन है। श्रीकृष्ण उसे क्षत्रिय धर्म का स्मरण कराते हैं और बताते हैं कि अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना ही सच्चा धर्म है। धर्मयुक्त युद्ध से पलायन करने पर कीर्ति, सम्मान और आत्मबल–तीनों का ह्रास होता है। कर्मयोग और निश्चयात्मक बुद्धि द्वितीय अध्याय में कर्मयोग का बीज प्रतिपादित करते हुए कहा गया– कर्म करो, फल की आसक्ति त्यागो। यही निश्चयात्मक बुद्धि है। स्थितप्रज्ञ पुरुष के लक्षणों का वर्णन करते हुए बताया गया कि जो व्यक्ति सुख-दुःख, लाभ-हानि, जय-पराजय में समभाव रखता है, वही ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करता है। विषय-विकार से विनाश तक की श्रृंखला कथा में यह भी बताया गया कि विषयों का ध्यान आसक्ति, काम, क्रोध, मोह, स्मृति भ्रंश, बुद्धि नाश सर्वनाश का कारण बनता है। इससे बचने का उपाय इंद्रिय संयम और भगवान में मन की स्थिरता बताया गया। ब्राह्मी स्थिति ही जीवन का लक्ष्य कथावाचक इं. देवेंद्र नाथ शुक्ला 'कृष्णार्पित' ने कहा कि द्वितीय अध्याय का सार यही है कि– जो व्यक्ति ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर लेता है, वह जीवन में कभी विचलित नहीं होता और अंततः परम गति को प्राप्त करता है। कथा के दौरान पंडाल में उपस्थित श्रद्धालु 'हरि-हरि', 'जय श्रीकृष्ण' और 'हर-हर गंगे' के जयघोष करते रहे। यह कथा न केवल शास्त्रीय ज्ञान का संप्रेषण है, बल्कि आज के युग में कर्तव्य, विवेक और आत्मबोध का सशक्त मार्गदर्शन भी है।

शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर ठगे गए रुपये को पुलिस ने कराया वापस

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के कुशल निर्देशन में साइबर क्राइम थाना भदोही द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर ठगी गई 1, 00, 646 रुपये की धनराशि पीड़ित के खाते में सुरक्षित वापस कराई गई। धनराशि वापस पाकर पीड़ित ने भदोही पुलिस का हृदय से आभार व्यक्त किया।

पुलिस अधीक्षक ने जनपद में बढ़ रहे साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए साइबर सेल, साइबर क्राइम थाना एवं हेल्प डेस्क को निर्देशित किया है कि धोखाधड़ी अथवा सोशल मीडिया के दुरुपयोग से जुड़े मामलों में त्वरित और प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

बताया गया कि वर्ष 2024 में वादी मुकदमा धर्मेंद्र यादव को आरोपियों ने विश्वास में लेकर शेयर मार्केट में पैसा लगाने के बहाने लगभग तीन लाख रुपये की ठगी की थी। इस संबंध में साइबर क्राइम थाना पर मु0अ0सं0-06/25, धारा 318(4), 319(2) बीएनएस एवं 66 आईटी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की गई। साइबर क्राइम थाना की टीम ने वादी द्वारा ट्रांसफर की गई धनराशि को एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से ट्रेस कर संबंधित बैंक खातों को होल्ड कराया तथा बैंकों से पत्राचार कराते हुए ठगी गई 1, 00, 646 रुपये की धनराशि पीड़ित के खाते में वापस कराई। अपनी धनराशि पुनः प्राप्त होने पर पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक भदोही, अपर पुलिस अधीक्षक एवं साइबर क्राइम थाना की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

शैक्षिक सत्र 2026-27 हेतु बाल मैपिंग को लेकर समीक्षा बैठक सम्पन्न

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। शैक्षिक सत्र 2026-27 के सुचारु एवं प्रभावी संचालन के उद्देश्य से मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ल की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक तथा जिला विकास अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में 01 अप्रैल 2026 को 06 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले समस्त बच्चों की बाल मैपिंग को समयबद्ध एवं शत-प्रतिशत पूर्ण करने पर विस्तृत चर्चा की गई। अवगत कराया गया कि जनपद स्तर पर बाल मैपिंग का कुल लक्ष्य 32, 170 बच्चों का निर्धारित किया गया है, जिसे विकास खंडों एवं शहरी क्षेत्रों के अनुसार विभाजित किया गया है।

मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि बाल मैपिंग का कार्य जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के समन्वय में विद्यालयों, शिक्षकों एवं संबंधित कार्मिकों द्वारा घर-घर सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र बच्चा विद्यालय में नामांकन से वंचित न रहे। सर्वेक्षण के दौरान बच्चों की आयु, अभिभावक विवरण एवं निवास संबंधी सूचनाओं का सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाए। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि बाल मैपिंग कार्य की नियमित समीक्षा की जाएगी तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। सभी विभागों को आपसी समन्वय से लक्ष्य की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। प्रशासन द्वारा अभिभावकों से अपील की गई है कि वे सर्वेक्षण टीमों को आवश्यक सहयोग एवं सही जानकारी प्रदान करें, ताकि प्रत्येक बच्चे का समय से विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित हो सके और 'हर बच्चा स्कूल में' के उद्देश्य को सफल बनाया जा सके।

मुरादाबाद ने गाजीपुर को 55 रन से जौनपुर ने मिर्जापुर को आठ विकेट से हराया

महर्षि आजाद राज्यस्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता के पांचवें दिन हुए रोमांचक मुकाबले

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। सुरियावां क्षेत्र स्थित महर्षि आज़ाद स्टेडियम, मेढ़ी में तेजधर ब्रह्मबाबा खेल समिति द्वारा आयोजित महर्षि आज़ाद राज्यस्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता के पाँचवे दिन गुरुवार को दो मुकाबले खेले गए, जिनमें दर्शकों को रोमांचक क्रिकेट देखने को मिला।

दिन का पहला मुकाबला मुरादाबाद व गाजीपुर के बीच खेला गया व दूसरा मैच मिर्जापुर व जौनपुर के बीच खेला गया।

पहले मुकाबले में मुरादाबाद की टीम ने गाजीपुर को 55 रनों से पराजित कर प्रतियोगिता में शानदार शुरुआत की। मुकाबले में मुरादाबाद की टीम ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में संतुलित प्रदर्शन किया।

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुरादाबाद की टीम ने निर्धारित 18 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 161 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। टीम की ओर से पार्व चौहान ने 29 गेंदों पर 52 रनों की आक्रामक पारी खेली, जबकि आशु दक्ष ने 30 रन बनाकर महत्वपूर्ण योगदान दिया। अन्य बल्लेबाजों ने भी जरूरत के अनुसार रन जोड़े। गाजीपुर की ओर से गेंदबाजी में आयुष चिंगारी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 विकेट झटके। इसके अलावा सोनू शर्मा, पवन कुमार, रोहित और शिवा ने भी कसी हुई गेंदबाजी कर मुरादाबाद

के बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी गाजीपुर की टीम की शुरुआत लड़खड़ाई और नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे। पूरी टीम 14.1 ओवर में 106 रन पर ऑलआउट हो गई। गाजीपुर की ओर से अमित यादव ने 31 रन तथा मो. आरिफ ने 28 रन की संघर्षपूर्ण पारी खेली, लेकिन टीम को हार से नहीं बचा सके।

मुरादाबाद की ओर से गेंदबाजी में अमित यादव ने 3 विकेट, जबकि अजय मौर्या और मो. आरिफ ने 2-2 विकेट लेकर गाजीपुर की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी।

इस जीत के साथ मुरादाबाद की टीम ने प्रतियोगिता में अपनी मजबूत दावेदारी पेश की। दूसरे मैच में मिर्जापुर की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 18 ओवरों में चार विकेट पर 154 रन बनाए।जबाब में जौनपुर के बल्लेबाज रौनक सिंह, मिथिलेश कुमार व गौरव सिंह के शानदार अर्धशतक की बदौलत 13 वे ओवर में दो विकेट की कीमत पर लक्ष्य प्राप्त कर लिया। मैच के दौरान मैदान पर बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे और रोमांचक मुकाबले का भरपूर आनंद लिया।आयोजन समिति के मुताबिक प्रतियोगिता का अगला मैच मुरादाबाद बनाम सेवाश्रम इंटर कालेज सुरियावां व दूसरा मैच शशांक इलेवन बनाम जौनपुर के बीच खेला जाएगा।

इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, सचिव अमर बहादुर सिंह, विजयशंकर राय, राजमणि पांडेय, राजकुमार सरोज, जेपी सिंह, सन्तोष पांडेय शास्त्री, श्याम बहादुर यादव, , परमेंद्र गौतम सहित बड़ी संख्या में खेल प्रेमी व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।

लिफ्ट के गड्ढे में गिरने से मजदूर की मौत

कोनगांव में बिल्डिंग निर्माण स्थल पर दर्दनाक हादसा

सुरक्षा इंतजामों की भारी कमी, ठेकेदार और सुपरवाइजर पर केस दर्ज।

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी तालुका के कोनगांव इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत में काम कर रहे 19 वर्षीय मजदूर की दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। लिफ्ट के खुले गड्ढे में गिरने से युवक की मौके पर ही जान चली गई। इस घटना ने एक बार फिर निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी को उजागर कर दिया है। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान सिकंदर जियालाल यादव (19) के रूप में हुई है। वह मूल रूप से झारखंड का निवासी था और रोज़गार के सिलसिले में भिवंडी के कोनगांव इलाके में मजदूरी कर रहा था। मृतक के पिता जयलाल सनिलाल यादव (43) की शिकायत पर कोनगांव पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। यह हादसा 6 जनवरी की दोपहर करीब 2:30 बजे हुआ। उस समय सिकंदर कोनगांव पुलिस चौकी के पास निर्माणाधीन एंटलाटीक टावर की निर्माणाधीन इमारत की चौथी मंजिल पर बेगारी का काम कर रहा था। काम के दौरान अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे लिफ्ट के खुले गड्ढे में गिर पड़ा।गिरने से सिकंदर को सिर, हाथ, कमर और पैरों में गंभीर चोटें आईं। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोप है कि निर्माण स्थल पर किसी भी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। न तो सेफ्टी बेल्ट उपलब्ध कराई गई थी और न ही लिफ्ट गड्ढे के आसपास बैरिकेड या चेतावनी संकेत लगाए गए थे। पुलिस जांच में सामने आया है कि निर्माण स्थल के ठेकेदार और सुपरवाइजर ने मजदूरों को आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए थे। लापरवाही के चलते हुई इस मौत को गंभीर अपराध मानते हुए पुलिस ने कुणाल अमरीशभाई बारनिया और रमेश शंकर पवार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 106(1) के तहत गैरइरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। कोनगांव पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा कर लिया है और निर्माण कंपनी से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि इससे पहले भी साइट पर सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया गया था या नहीं। इस दर्दनाक हादसे के बाद इलाके में काम कर रहे मजदूरों और सामाजिक संगठनों में रोष है। लोगों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई और मृतक के परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है।

कामतघर में दिनदहाड़े घर में सेंधमारी, नकदी और सोने के गहने उड़ा ले गए चोर

बंद घर को बनाया निशाना, इलाके में हड़कंप

भिवंडी। भिवंडी शहर के कामतघर इलाके में दिनदहाड़े हुई चोरी की एक सनसनीखेज वारदात से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। अज्ञात चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाते हुए नकदी और सोने के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से कामतघर और आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार भाग्यनगर, कामतघर की चाली में रहने वाली 30 वर्षीय गायत्री संतोष पाणिग्राही एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं। वह 21 जनवरी की सुबह काम पर चली गई थीं। इसी दौरान सुबह करीब 9 बजे से दोपहर 1:30 बजे के बीच किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके घर के पीछे के दरवाजे से जबरन प्रवेश किया। चोरों ने सीधे बेडरूम में रखी लकड़ी की अलमारी को खंगाला और उसमें रखी दो सोने की चूड़ियां, जिनकी कीमत करीब 52 हजार रुपये बताई जा रही है, साथ ही नकदी चोरी कर ली। चोरी गए माल की कुल कीमत लगभग 77 हजार रुपये आंकी गई है। दोपहर में जब गायत्री पाणिग्राही घर लौटीं तो उन्होंने घर का सामान बिखरा हुआ पाया। इसके बाद उन्होंने तत्काल भिवंडी शहर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का पंचनामा किया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। भिवंडी शहर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 305 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। इधर दिनदहाड़े हुई इस चोरी की घटना के बाद स्थानीय नागरिकों में भय का माहौल है। रहवासियों ने पुलिस से इलाके में गश्त बढ़ाने और संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखने की मांग की है।

8 लोगों पर बिजली चोरी का मामला दर्ज

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। भिवंडी तालुका के कोनगांव में बिजली चोरी का एक बड़ा और संगठित मामला सामने आया है, जिसने बिजली वितरण कंपनी के साथ-साथ आम उपभोक्ताओं को भी झटका दिया है। शांतीनगर पुलिस थाने में दर्ज दो अलग-अलग मामलों में यह खुलासा हुआ है कि कई लोगों ने जानबूझकर मीटर से छेड़छाड़ कर और अवैध तारों के जरिए सीधे लाइन से बिजली खींचकर लाखों रुपये की बिजली चोरी की।

पहले मामले में शिकायतकर्ता धनंजय देवराम पाटिल (40), जो महावितरण कंपनी में कार्यरत हैं, ने अगस्त 2023 से जुलाई 2025 के बीच कौस्तुभा व्हीला,पाचमार नगर, आदिवासी पाडा, गोकुल नगर इलाके में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, इस इलाके के कई फ्लैटों में रहने वाले उपभोक्ताओं ने अपने बिजली मीटर को बायपास कर सीधे महा वितरण लाइन से अवैध केबल जोड़ रखे थे। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने कुल 15,313 यूनिट बिजली की चोरी की, जिसकी कीमत करीब 2,98,010 आंकी गई है। इस मामले में सात उपभोक्ताओं के नाम आरोपी के तौर पर दर्ज किए गए हैं, जिनमें सुरेश पाटिल, मणिक म्हात्रे, मुकेश बारक्या, रुपेश अभिमन्यु, निलेश म्हात्रे,कल्पेश बारक्या और संकेत सुनील म्हात्रे शामिल हैं। सभी पर भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत केस दर्ज किया गया है।

दूसरा मामला भी उतना ही गंभीर है। इसमें शिकायतकर्ता धनंजय पाटिल ने बताया कि जनवरी 2024 से दिसंबर 2025 के बीच कोनगाव इलाके के पीर शाहबुल हुसैन मंज़िल में रहने वाले अम्मात अब्दुल एस कुंगले और रकीजा अब्दुल एम कुंगल ने अपने मीटर से छेड़छाड़ कर सीधे बिजली लाइन से कनेक्शन लिया। जांच में पाया गया कि इस अवैध कनेक्शन से 12,086 यूनिट बिजली की चोरी की गई, जिससे बिजली कंपनी को करीब 3,63,310 का नुकसान हुआ। बिजली वितरण कंपनी की तकनीकी टीम द्वारा मौके पर की गई जांच में अवैध केबल, कट-आउट से जुड़ी लाइनें और मीटर से छेड़छाड़ के ठोस सबूत मिले। इसके बाद पुलिस ने दोनों मामलों में एफआईआर दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। शांतिनगर के सहायक पुलिस निरीक्षक अरूण घोलप कर रहे है। भिवंडी में बार-बार सामने आ रहे बिजली चोरी के मामलों ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या कुछ इलाकों में अवैध बिजली नेटवर्क पनप रहा है। पुलिस और बिजली कंपनी अब संयुक्त रूप से ऐसे कनेक्शनों की पहचान कर बड़े स्तर पर कार्रवाई की तैयारी में हैं।

फ्लैट दिलाने का झांसा देकर 65 लाख की ठगी

भिवंडी में रियल एस्टेट फ्रॉड का बड़ा मामला

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। भिवंडी में घर खरीदने का सपना देखने वाले एक व्यक्ति के साथ 65 लाख रुपये की बड़ी ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। फ्लैट दिलाने का झांसा देकर दो लोगों ने ऑनलाइन और नकद रूप में मोटी रकम ऐंठ ली और फिर न तो फ्लैट दिलाया और न ही पैसे लौटाए। निजामपुरा पुलिस थाने में दर्ज इस केस ने इलाके में रियल एस्टेट के नाम पर चल रही ठगी की पोल खोल दी है।

पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता सुमित विकास वडके (39), जो पेशे से कपड़ा डाइंग कंपनी का व्यवसायी हैं और भिवंडी के गोकुल नगर स्थित पारिजात बिल्डिंग में रहते हैं, को आरोपियों ने मुंबई के विलेपार्ले इलाके में एक फ्लैट दिलाने का लालच दिया। आरोपियों सिद्धार्थ बिहानी (41) और प्रकाश बिहानी (75), निवासी जुहू, मुंबई ने खुद को रियल एस्टेट से जुड़ा बताते हुए आकर्षक डील का भरोसा दिलाया। शिकायत के मुताबिक, 1 मई की सुबह करीब 9 बजे आरोपियों ने भिवंडी स्थित सुमित के घर पर आकर फ्लैट की डील पक्की करने का नाटक किया। इसी दौरान उन्होंने दस्तावेज़ और बुकिंग के नाम पर शिकायतकर्ता से 65 लाख रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर और नकद के रूप में ले लिए। बाद में जब सुमित ने फ्लैट के कागज़ात और कब्ज़े के बारे में पूछा, तो दोनों आरोपी टालमटोल करने लगे। कुछ समय बाद यह साफ हो गया कि न तो कोई फ्लैट बुक हुआ था और न ही आरोपियों का किसी प्रोजेक्ट से कोई लेना-देना था। अपने साथ धोखाधड़ी का एहसास होने पर सुमित वडके ने 21 जनवरी को निजामपुरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 34 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद भिवंडी और आसपास के इलाकों में रियल एस्टेट के नाम पर चल रही ठगी को लेकर लोगों में चिंता बढ़ गई है। इस घटना की जांच अपराध शाखा युनिट 2 की पुलिस कर रही है।

भिवंडी में वाहन चोरों का कहर, एक ही दिन में बाइक और ऑटो रिक्शा चोरी

अलग-अलग इलाकों से महंगी मोटरसाइकिल और रिक्शा गायब, पुलिस जांच में जुटी।

भिवंडी। भिवंडी शहर में वाहन चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामलों में एक ही दिन अलग-अलग इलाकों से एक महंगी मोटरसाइकिल और एक ऑटो-रिक्शा चोरी होने की घटनाएं सामने आई हैं। इन वारदातों के बाद नागरिकों में दहशत का माहौल है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं।

पहला मामला नारपोली पुलिस थाना क्षेत्र का है। अंजुरफाटा स्थित शिवाजी नगर निवासी जयशंकर रामविलास झा (34) ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी काले रंग की येज़्दी जावा मोटरसाइकिल (श्प्-04-श्भ्-5354) चुर डांईग समोर, अंजुरफाटा-वसई रोड पर पार्क की थी। 19 जनवरी की सुबह करीब 7:30 बजे से 20 जनवरी की शाम 6:30 बजे के बीच किसी अज्ञात चोर ने उनकी बाइक चुरा ली। चोरी गई बाइक की कीमत करीब 2 लाख 20 हजार रुपये बताई जा रही है।

दूसरी घटना शांतीनगर पुलिस थाना क्षेत्र की है। शिकायतकर्ता अफजल फिरोज फुलवाला (32), जो पेशे से ऑटो-रिक्शा चालक हैं और कल्याण पूर्व के गोविंद वाड़ी इलाके में रहते हैं, ने बताया कि उन्होंने अपना रिक्शा (MH-05-DL-3991)

नेशनल मार्बल की दुकान के पास बस स्टॉप के नजदीक खड़ा किया था। 19 जनवरी की रात करीब 8:30 बजे से 9:50 बजे के बीच अज्ञात चोर उनका ऑटो-रिक्शा चोरी कर फरार हो गया। रिक्शा की कीमत लगभग 50 हजार रुपये आंकी गई है। दोनों मामलों में संबंधित पुलिस थानों ने अज्ञात चोरों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 303(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और वाहन चोर गिरोह की भूमिका की भी जांच की जा रही है। लगातार बढ़ रही वाहन चोरी की घटनाओं से स्थानीय नागरिकों में असुरक्षा की भावना बढ़ गई है। लोगों ने पुलिस से रात्रि गश्त बढ़ाने और चोरी की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

राज्य की 29 महानगरपालिकाओं के महापौर पदों का आरक्षण घोषित

15 महानगरपालिकाओं में महिला महापौर होंगी

भिवंडी। महाराष्ट्र राज्य की 29 महानगरपालिकाओं के महापौर पदों के लिए आरक्षण की घोषणा कर दी गई है। नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाल की अध्यक्षता में आरक्षण की यह सोडत (लॉटरी प्रक्रिया) संपन्न हुई। यह आरक्षण आगामी ढाई वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेगा। खास बात यह है कि 29 में से 15 महानगरपालिकाओं में विभिन्न वर्गों की महिलाएं महापौर पद की जिम्मेदारी संभालेंगी।

राज्य सरकार द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के लिए केवल एक महापौर पद आरक्षित किया गया है। नियमों के अनुसार अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग के लिए इस बार कोई पद आरक्षित नहीं हुआ है। अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग के लिए कुल तीन पद आरक्षित किए गए हैं, जिनमें से दो पद अनुसूचित जाति महिला वर्ग के लिए हैं।

नागरिकों के पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए कुल आठ महापौर पद आरक्षित किए गए हैं। इनमें से चार पद नागरिकों के पिछड़ा वर्ग (महिला) के लिए और चार पद नागरिकों के पिछड़ा वर्ग (सामान्य) के लिए रखे गए हैं। इसके अलावा शेष 17 महानगरपालिकाओं में से नौ महापौर पद सामान्य महिला वर्ग के लिए तथा आठ पद सामान्य (खुला) वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं।

महापौर पद के लिए आरक्षित महानगरपालिकाएं.....

अनुसूचित जनजाति (एसटी)
- कल्याण-डोंबिवली

अनुसूचित जाति (एससी)
- ठाणे (सामान्य)
- जालना (महिला)
- लातूर (महिला)

नागरिकों का पिछड़ा वर्ग (महिला)
- जळगांव
- चंद्रपुर
- अहिल्यानगर
- अकोला

नागरिकों का पिछड़ा वर्ग (सामान्य)
- पनवेल
- इचलकरंजी
- कोल्हापुर
- उल्हासनगर

सामान्य महिला वर्ग
- पुणे
- धुळे
- बृहन्मुंबई
- नवी मुंबई
- नांदेड-वाघाळा
- मालेगांव
- मीरा-भाईंदर
- नागपुर
- नाशिक

सामान्य (खुला) वर्ग
- छत्रपति संभाजीनगर
- परभणी
- सांगली-मिरज-कुपवाड
- अमरावती
- वसई-विरार
- सोलापुर
- पिंपरी-चिंचवड
- भिवंडी-निजामपुर

इस आरक्षण की घोषणा के बाद राज्य की राजनीति और स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में हलचल तेज हो गई है। विशेष रूप से महिला आरक्षण की संख्या अधिक होने से महिला नेतृत्व को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। राजनीतिक दल अब अपने-अपने उम्मीदवारों की रणनीति तय करने में जुट गए हैं।

पलासवाड़ा के पास स्थित लेवल क्रॉसिंग पर ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल पर प्रतापनगर-एकतानगर खंड पर संरक्षा में वृद्धि एवं ट्रेनों की गति बढ़ाने के उद्देश्य से अनेक महत्वपूर्ण कार्य प्रगति पर हैं।इसी क्रम में डभोई के पलासवाड़ा के पास स्थित लेवल क्रॉसिंग यानि समपार फाटक संख्या 20 पर एक रोड ओवर ब्रिज (ँ)का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण कार्य के दौरान सड़क यातायात को सुचारु बनाए रखने हेतु रेलवे द्वारा एक डाइवर्जन रोड विकसित की गई है। जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक संघटनों द्वारा इस लेवल क्रॉसिंग पर ट्रैफिक जाम की समस्या से निजाद के लिए डाइवर्जन रोड को और चौड़ा करने की मांग पर अमल करते हुए वडोदरा मंडल द्वारा तेज गति से कार्य शुरू कर दिए है।

LC-20 (पलासवाड़ा) लेवल क्रॉसिंग पर वडोदरा की ओर जाने वाले मार्ग के एग्जिट पर स्थित स्पीड ब्रेकर को हटा दिया गया है, जिससे वाहनों के रुकने का समय कम हुआ है। इसी प्रकार, डभोई की ओर से आने वाली पुरानी सड़क पर भी स्पीड ब्रेकर को हटाया गया है। इसके अतिरिक्त सड़क की खराब एवं ऊबड़-खाबड़ सतह को दुरुस्त करते हुए पुनः डामरीकरण किया गया है।

पलासवाड़ा लेवल क्रॉसिंग पर पहले लिफ्टिंग बैरियर (बूम) की लंबाई मात्र 6.50 मीटर थी,जिसे अब वडोदरा मंडल के इंजीनियरिंग विभाग तथा गुजरात राज्य सरकार के सड़क एवं भवन विभाग द्वारा संयुक्त स्थल निरीक्षण के उपरांत बढ़ाकर 8.20 मीटर कर दिया गया है। इसके फलस्वरूप अब डभोई एवं वडोदरा दोनों दिशाओं से आने वाले वाहनों के लिए पृथक-पृथक लगभग 8.00 मीटर चौड़ा सड़क मार्ग उपलब्ध हो सकेगा, जिससे यातायात प्रवाह में उल्लेखनीय सुधार होगा।

गुजरात राज्य सरकार वे R&B विभाग द्वारा अप्रोच रोड को और चौड़ा करने का कार्य भी प्रगति पर है। चौड़ीकरण कार्य पूर्ण होने के पश्चात रेलवे द्वारा सड़क के किनारे 100 मीटर एवं 200 मीटर की दूरी पर लेवल क्रॉसिंग संकेतक बोर्ड लगाए जाएंगे,जिनका निर्माण कार्य पहले ही पूर्ण कर लिया गया है। साथ ही,दृश्यता बढ़ाने के उद्देश्य से हाइट गेज पर भी पेंटिंग की गई है।

वडोदरा मंडल द्वारा उठाए गए इन समन्वित और सुधारात्मक कदमों से आने वाले दिनों में पलासवाड़ा लेवल क्रॉसिंग पर यातायात जाम की समस्या से आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी।

भिवंडी में विवाहित महिला से बर्बरता

ससुराल वालों पर मारपीट और जान से मारने की धमकी का केस दर्ज

घरेलू हिंसा का गंभीर मामला, पति समेत चार आरोपी नामजद

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी शहर में घरेलू हिंसा का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर उसके पति, ननद और अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज, दहेज मांगने और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है। घटना खंडूपाड़ा स्थित असारी मोहल्ला इलाके की बताई जा रही है।

पुलिस के अनुसार 27 वर्षीय महिला, जो मंगल बाजार स्लम पर रहती है, ने भिवंडी शहर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता का आरोप है कि उसके पति इमरान अहमद खान, ननद आफरीन आदिल अंसारी, गुलनाज अतीक अंसारी और अल्मास अहमद खान ने मिलकर उसे लंबे समय से मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। शिकायत में बताया गया है कि ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा मामूली बातों को लेकर झगड़ा करते, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। आरोप है कि पीड़िता को बेरहमी से पीटा गया, उसका गला दबाने की कोशिश की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि उसके पति ने उससे जबरन मायके से बुलेट मोटरसाइकिल खरीदने के लिए पैसा लाने की मांग की। विरोध करने पर आरोपियों ने उसके साथ और अधिक अत्याचार किए। घटना के बाद पीड़िता ने पुलिस से संपर्क कर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर भिवंडी शहर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 85, 115(2), 351(3) और 352(4),3(5) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस द्वारा इस मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। सभी आरोपियों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है और जल्द ही उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। इस घटना ने एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा और घरेलू हिंसा जैसे गंभीर सामाजिक मुद्दे पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

‘शंकराचार्य का अपमान, नही सहेगा हिंदुस्तान’

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में सपा ने लगाए पोस्टर

लखनऊ (**एजेंसी**)। प्रयागराज माघ मेले में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की पालकी रोके जाने को लेकर घटित घटना के विरोध में समाजवादी पार्टी (सपा) मैदान में उतर आई है। पार्टी कार्यालय के बाहर अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में समाजवादी छात्रसभा के पूर्व प्रदेश सचिव आशुतोष सिंह ने पोस्टर लगाया है। पोस्टर पर ‘शंकराचार्य का अपमान, नही सहेगा हिंदुस्तान’ लिख कर समर्थन दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर लगातार भाजपा सरकार पर हमलावर हैं। भाजपा को घेरने के लिए अखिलेश यादव कोई मौका नही चूक रहे हैं। अभी दो दिन पहले ही फोन पर शंकराचार्य से बात कर उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाने की बात कही गई थी। इसी क्रम में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने शंकराचार्य से प्रयागराज माघ मेले में मुलाकात की थी। एक दिन पूर्व अखिलेश यादव ने बयान जारी कर कहा था कि यदि कोई अधिकारी शंकराचार्य से परिचय और प्रमाण-पत्र मांग रहा है, तो सनातन धर्म का इससे बड़ा अपमान कोई और नहीं हो सकता है। भाजपा सरकार ने सनातन धर्म, शंकराचार्य, साधु-संतों, माघ मेला और देश का अपमान किया है।

भाजपा मीडिया विभाग प्रमुख नवनाथ बन का तीखा हमला

2019 में भाजपा से विश्वासघात का फल अब ‘उबाठा’ को कल्याण में मिला

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

2019 के विधानसभा चुनाव भाजपा के साथ मिलकर लड़ने के बावजूद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद के लालच में तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ विश्वासघात किया। उसी विश्वासघात का परिणाम आज ‘उबाठा’ गुट को कल्याण में भुगतना पड़ा है।

‘जैसे कर्म, वैसे फल’ – यह कहावत अब उद्धव ठाकरे और संजय राऊत को भली-भांति समझ में आ गई होगी, ऐसा तीखा प्रहार भाजपा मीडिया विभाग प्रमुख नवनाथ बन ने गुरुवार को किया।

भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए नवनाथ बन ने कहा कि जिन लोगों को नैतिकता का अर्थ तक नहीं पता, वही आज मनसे को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। संजय राऊत और उबाठा गुट का यह आचरण हास्यास्पद है।

उन्होंने कहा कि 2019 में सत्ता के लिए देवेंद्र फडणवीस की पीठ में छुरा घोंपने वालों को आज कल्याण-डोंबिवली में मनसे द्वारा भाजपा-शिवसेना महायुति को समर्थन दिए जाने पर नैतिकता की याद आ रही है। उद्धव ठाकरे और संजय राऊत को नैतिकता पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। कल्याण-डोंबिवली में मनसे ने विकास और हिंदुत्व के लिए महायुति को समर्थन दिया है।

नवनाथ बन ने कहा कि मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, ठाणे, नवी मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में जनता ने महायुति को स्पष्ट जनादेश दिया है। आगामी जिला परिषद चुनावों में भी मतदाता उबाठा गुट को घर बैठाने का काम करेंगे। विकास से उबाठा गुट और संजय राऊत का कोई लेना-देना

नहीं है। उन्हें विकास नहीं बल्कि कमीशन, खंडणी, भ्रष्टाचार और घोटालों की ही भाषा समझ में आती है। इसलिए ही संजय राऊत को ‘विकास’ शब्द भी असंसदीय लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विकास का पर्याय बन चुके हैं, यह समीकरण जनता के मन में पूरी तरह स्थापित हो चुका है।

हार के बाद ‘जनाब सेना’ को अचानक साधु-संत याद आए

महानगरपालिका चुनावों में हिंदुत्ववादी मतदाताओं द्वारा करारी हार मिलने के बाद संजय राऊत को अचानक साधु-संतों से प्रेम उमड़ पड़ा है। मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति के लिए जिन उद्धव ठाकरे और राऊत ने वंदनीय बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना को ‘जनाब सेना’ में बदल दिया, उन्हें पराजय के बाद साधु-संतों की याद आ रही है।

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के कथित अपमान पर राऊत का अचानक साधु-संतों के पक्ष में आना आश्चर्यजनक है। देर से ही सही, लेकिन राऊत को सद्बुद्धि आई है – ऐसा कटाक्ष भी नवनाथ बन ने किया। उन्होंने कहा कि इस कथित अपमान की जांच होगी, लेकिन उबाठा सरकार के समय पालघर में हुए साधु हत्या कांड पर उद्धव ठाकरे और संजय राऊत ने एक शब्द तक नहीं कहा था और न ही दोषियों को सजा दिलाने के लिए कोई प्रयास किया था।

उबाठा गुट ने मनसे का ‘केसाने गला घोंटा’

नवनाथ बन ने आरोप लगाया कि उबाठा गुट ने मनसे का भारी नुकसान किया है। इस बार उबाठा सेना के साथ गठबंधन के बावजूद मुंबई में मनसे के केवल 6 नगरसेवक चुने गए, जबकि पिछली बार बिना गठबंधन के मनसे के 7 नगरसेवक निर्वाचित हुए थे।

जब स्थिति सामान्य हो जाएगी

तब 'असीमित अधिकार' को लेकर सच्चाई सामने आ जाएगी : गंभीर

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। भारतीय कोच गौतम गंभीर ने इस प्रचलित धारणा को खारिज कर दिया है कि टीम चयन में उनके पास 'असीमित अधिकार' हैं और कांग्रेस सांसद शशि थरूर द्वारा उनकी भूमिका को 'प्रधानमंत्री के बाद सबसे मुश्किल काम' बताने के बाद खुद को 'अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा किए जाने' पर उन्होंने हैरानी जताई है।

क्रिकेट के शौकीन थरूर ने नागपुर में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच से पहले गंभीर के साथ एक सेल्फी साझा की और पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज की लगातार आलोचनाओं के बावजूद अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उनकी प्रशंसा व्यक्त की।

थरूर ने ट्वीट किया, "नागपुर में मेरे पुराने मित्र गौतम गंभीर के साथ अच्छी और खुलकर बातचीत का आनंद लिया, जो प्रधानमंत्री के बाद भारत में सबसे मुश्किल काम संभाल रहे हैं। लाखों लोग रोजाना उन पर सवाल उठाते हैं, लेकिन वे शांत रहते हैं और पूरी निर्भीकता के साथ अपने काम को अंजाम देते हैं। उनके शांत दृढ़ संकल्प और सक्षम नेतृत्व के लिए प्रशंसा के कुछ शब्द। उन्हें आज से ही सभी सफलताओं की शुभकामनाएं।"

गंभीर ने इस पर देर रात जवाब दिया और उन कुछ चर्चाओं का जिक्र किया जो उनके कार्यकाल में हावी रही हैं। गंभीर ने एक्स पर लिखा, "डॉ. शशि थरूर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जब मामला शांत हो जाएगा तब कोच के कथित 'असीमित अधिकार' को लेकर सच्चाई और तर्क स्पष्ट हो जाएंगे। तब तक मुझे खुद के खिलाफ खड़ा देखकर हंसी आ रही है।" जब से गंभीर ने भारतीय टीम की कमान संभाली है, तब से टीम में तीनों प्रारूपों में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। सूर्यकुमार यादव को भारत का टी20 कप्तान नियुक्त करने से लेकर रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने तक टीम में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। इस दौरान शुभमन गिल को टेस्ट और वनडे टीम का कप्तान भी नियुक्त किया गया था।

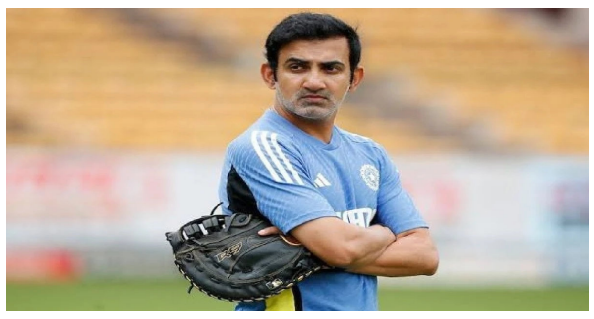

पीसीबी का भारत पर 'विज्ञापन वार'

भारत की हाथ मिलाने की कोई नीति नहीं पर पाकिस्तान ने कसा तंज, नए वीडियो से छिड़ा विवाद

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का मैदान हो या विज्ञापनों की दुनिया, तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी आगामी टी -20 सीरीज के लिए एक प्रोमो जारी किया है, जिसने एक नया विवाद छेड़ दिया है। इस वीडियो में सीधे तौर पर भारतीय क्रिकेट टीम की 'नो-हैंडशेक' (हाथ न मिलाने की) पॉलिसी पर तंज कसा गया है। प्रोमो में पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलियाई फैंस के लिए एक मेहमाननवाज़ मेज़बान के तौर पर दिखाया गया है, जिसमें एक्टर्स देश घूमते हुए दिखाए गए हैं। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा वीडियो में थोड़ी देर के लिए दिखते हैं और मेहमाननवाज़ी के मैसेज को मज़बूत करते हैं।

पीसीबी द्वारा जारी किए गए इस विज्ञापन में पाकिस्तान की मेहमाननवाज़ी को दिखाया गया है। वीडियो के अंत में एक दृश्य है जहाँ एक विदेशी पर्यटक कैब से उतरता है, लेकिन ड्राइवर से हाथ मिलाना भूल जाता है। तभी ड्राइवर उसे वापस बुलाकर कहता है: 'हैंडशेक भूल गए आप, शायद हमारे पड़ोसियों के यहाँ रुके थे।' यह सीधा हमला भारतीय टीम के उस हालिया फैसले पर है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाना बंद कर दिया है। भारत ने एशिया कप 2025 के दौरान पाकिस्तान के साथ नो-हैंडशेक पॉलिसी शुरू की थी, जब भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कट्टर प्रतिद्वंद्वियों के बीच तीनों मैचों के दौरान आगा से हाथ मिलाने से मना कर दिया था। यह फिर कोलंबो में महिला विश्व कप मैच तक फैल गया जब हरमनप्रीत कौर ने पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना से हाथ नहीं मिलाया। राइजिंग स्टार्स एशिया कप और अंडर -19 एशिया कप मैचों में भी भारतीय टीम ने ऐसा ही रुख अपनाया, क्योंकि उन्होंने इस हावभाव का इस्तेमाल भारतीय सेना और पहलगाम हमले के पीड़ितों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए किया।

ऑस्ट्रेलियन ओपन : जोकोविच ने मास्ट्रेली को हराकर तीसरे राउंड में बनाई जगह

मेलबर्न **(एजेंसी)**। सर्बिया के दिग्गज नोवाक जोकोविच ने गुरुवार को इटली के फ्रांसेस्को मास्ट्रेली को सीधे सेटों में हराकर 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन के तीसरे राउंड में जगह बनाई। आज यहां रॉड लेवर एरिना में खेले गये मुकाबले में सर्बियाई चौथी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी जोकोविच को एकल में 6-3, 6-2, 6-2 से जीत हासिल करने में कोई परेशानी नहीं हुई।

उन्होंने पहले सेट में 3-0 की बढ़त बनाकर कोटर् पर अपना दबदबा बनाया। मास्ट्रेली ने कुछ प्रतिरोध दिखाया, कई ब्रेक पॉइंट बचाए और शक्तिशाली सर्व और तीन ऐस लगाकर जोकोविच को सेट के लिए सर्व करने पर मजबूर किया। दूसरे सेट में भी पैटर्न वैसा ही रहा, जोकोविच ने 3-2 के बाद बढ़त बनाई और 6-2 से सेट जीत लिया। तीसरे सेट में जोकोविच ने मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, एक तनावपूर्ण पांचवें गेम में सर्व ब्रेक करके 4-1 से आगे हो गए। मास्ट्रेली ने देर से वापसी की कोशिश किया, लेकिन जोकोविच की सटीकता और निरंतरता निर्णायक साबित हुई, क्योंकि उन्होंने इतालवी खिलाड़ी की गलतियों का फायदा उठाकर जीत पूरी की।

जोकोविच ने एक अनजान विरोधी के बारे में कहा, 'आजकल मेरे साथ ऐसा अक्सर होता है। फिर भी, सम्मान हमेशा रहता है और मैं किसी को कम नहीं आंकता। उसके पास एक बड़ी सर्व है और बड़े स्टेज पर उसके पास अभी भी अनुभव की कमी है, लेकिन उसके पास गेम है जिससे वह बहुत आगे जा सकता है और रैंकिंग में ऊपर जा सकता है, इसलिए मैं उसे इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं।' जोकोविच तीसरे राउंड में नीदरलैंड के बोटिक वैन डी जैंड्सचल्प से भिड़ेंगे।

रोहित शर्मा को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की जाएगी

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। भारत के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा को क्रिकेट में उनके "अतुलनीय योगदान" और "अनुकरणीय नेतृत्व" के लिए शनिवार को यहां अजींक्या डीवाई पाटिल विश्वविद्यालय (एडीवाईपीयू) के दीक्षांत समारोह में मानद डॉक्टरेट (डी.लिट.) की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा।

विश्वविद्यालय ने बुधवार को घोषणा की कि उसके ऐतिहासिक 10वें दीक्षांत समारोह में रोहित प्रमुख आकर्षण होंगे। विश्वविद्यालय ने कहा, "प्रशंसक उन्हें क्रिकेट के हिटमैन के रूप में जानते हैं, लेकिन दीक्षांत समारोह रोहित शर्मा के लिए एक अलग तरह का मील का पत्थर है। रोहित को इस समारोह में खेल जगत में उनके अद्वितीय योगदान और विश्व मंच पर उनके अनुकरणीय नेतृत्व के लिए मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा।" टी20 अंतरराष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके 38 वर्षीय रोहित अब भारत की तरफ से केवल वनडे क्रिकेट में ही खेलते हैं।

बाबर आजम ने बीबीएल बीच में छोड़ा खराब आंकड़ों के साथ लौटे पाकिस्तान

सिडनी **(एजेंसी)**। सिडनी सिक्सर्स ने गुरुवार को कहा कि बाबर आजम बिग बैश लीग (बीबीएल 15) फाइनल सीरीज के बाकी मैचों के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे क्योंकि वह आने वाले इंटरनेशनल मैचों की तैयारी शुरू करने के लिए अपनी नेशनल टीम में शामिल होने के लिए पाकिस्तान लौट रहे हैं। सिक्सर्स ने पुष्टि की है कि डेनियल ह्यूजेस टीम में बाबर की जगह लेंगे और सीधे ओपनर के तौर पर खेलेंगे।

सिक्सर्स ने एक बयान में कहा, 'आने वाले इंटरनेशनल मैचों से पहले बाबर आज़म को पाकिस्तान के नेशनल कैंप में शामिल होने के लिए वापस बुलाया गया है। वह बीबीएल 15 फाइनल सीरीज़ के बाकी मैचों के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे।' बाबर ने बीबीएल क्लब में रहने के दौरान अपने सपोर्ट के लिए सभी फैंस को धन्यवाद भी दिया। सिक्सर्स द्वारा एक्स पर शेयर किए गए एक वीडियो में उन्होंने कहा, 'सबसे पहले मुझे मौका देने के लिए सिडनी सिक्सर्स का बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी लड़कों और सभी कोचों के साथ मैंने अपने समय का बहुत आनंद लिया। दुर्भाग्य से अब मुझे नेशनल ड्यूटी के लिए टीम छोड़नी होगी।'

उन्होंने आगे कहा, 'मुझे बहुत सी चीजें घर वापस ले जानी हैं। बहुत सी पॉजिटिव चीजें, इसलिए मैंने इसका बहुत आनंद लिया। खासकर, सिडनी सिक्सर्स के फैंस को धन्यवाद; हमेशा सपोर्ट रहता है, बहुत मजा आता है, मैंने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में उस माहौल का बहुत आनंद लिया, इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद।' बाबर मौजूदा सीजन में रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने 11 मैचों में सिर्फ 202 रन बनाए। उनका कम स्ट्राइक रेट 103.06 टीम के लिए चिंता का विषय था। पाकिस्तान 7 फरवरी को नीदरलैंड के खिलाफ टी20 विश्व कप में अपना अभियान शुरू करेगा। वे इस बड़े टूर्नामेंट की तैयारी के लिए 29 जनवरी से घर पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की टी20 आई सीरीज खेलेंगे।

टूटी सीटें और गंदे वॉशरूम, कंज़्यूमर कोर्ट ने एयर इंडिया पर ठोका 1.5 लाख जुर्माना

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। लंबी अंतरराष्ट्रीय उड़ान के दौरान यात्रियों को घटिया सुविधाएं देने के मामले में दिल्ली की एक डिस्ट्रिक्ट कंज़्यूमर कोर्ट ने एयर इंडिया को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने एयरलाइन को एक यात्री और उनकी बेटी को कुल ?1.5 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह आदेश नई दिल्ली स्थित डिस्ट्रिक्ट कंज़्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन-6 ने दिया। आयोग ने माना कि फ्लाइट के दौरान यात्रियों को जिन सुविधाओं का वादा किया गया था, वे उपलब्ध नहीं कराई गईं, जो सेवा में गंभीर कमी का मामला है।

यात्री और उनकी बेटी ने शिकायत में बताया कि लंबी इंटरनेशनल फ्लाइट के दौरान सीटें टूटी हुई थीं और आरामदायक नहीं थीं। इन-फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम काम नहीं कर रहा था, वॉशरूम बेहद गंदे थे, विमान के अंदर बदबू थी और परोसा गया खाना भी खराब गुणवत्ता का था। आरोप है कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद केबिन क्रू की ओर से कोई मदद नहीं मिली।

कमीशन की अध्यक्ष पूनम चौधरी और सदस्य शेखर चंद्र की बेंच ने 14 जनवरी को दिए अपने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता को मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए मुआवजा पाने का पूरा अधिकार है। आयोग ने कहा कि यात्रियों से जिन सुविधाओं के लिए शुल्क लिया गया, वे उन्हें दी ही नहीं गईं।

आदेश के मुताबिक, एयर इंडिया को शिकायतकर्ता और उनकी बेटी को ?50, 000-?50, 000 मुआवजे के तौर पर, जबकि ?50, 000 मुकदमे के खर्च के रूप में चुकाने होंगे।

यह मामला ग्रीन पार्क एक्सटेंशन निवासी शैलेंद्र भटनागर की शिकायत पर सामने आया। उन्होंने सितंबर 2023 में अपनी बेटी के साथ मेक माय ट्रिप के जरिए बुक किए गए इकोनॉमी क्लास टिकट पर एयर इंडिया की दिल्ली-न्यूयॉर्क-दिल्ली फ्लाइट से यात्रा की थी। एयर इंडिया ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उड़ान से पहले विमान की नियमित तकनीकी जांच की गई थी और उसे उड़ान के लिए पूरी तरह फिट पाया गया था। एयरलाइन ने यह भी दावा किया कि शिकायतकर्ता ने बिजनेस क्लास में अपग्रेड की मांग की थी लेकिन सीट उपलब्ध न होने के कारण ऐसा नहीं हो सका।

डाक विभाग का लक्ष्य वित्त वर्ष 2025-26 में राजस्व में 30 प्रतिशत की वृद्धि करना : सिंधिया

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बृहस्पतिवार को कहा कि डाक विभाग ने चालू वित्त वर्ष में राजस्व में 30 प्रतिशत की वृद्धि हासिल करने का लक्ष्य रखा है। डाक विभाग (डीओपी) की 2025-26 तीसरी (अक्टूबर-दिसंबर) तिमाही समीक्षा के बाद मंत्री ने कहा कि छह में से पांच क्षेत्रों के राजस्व में वृद्धि दर्ज की गई जबकि अमेरिकी सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण अंतरराष्ट्रीय डाक का राजस्व स्थिर रहा। सिंधिया ने कहा, " 2025-26 के लिए हमारा लक्ष्य 17, 546 करोड़ रुपये है जिसका मतलब है कि हम वित्त वर्ष 2024-25 के 13, 240 करोड़ रुपये से एक ही वित्त वर्ष में राजस्व में 30 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य रख रहे हैं।"

उन्होंने कहा कि 2023-2024 में यह 12, 800 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 13, 240 करोड़ रुपये हुआ जो केवल तीन प्रतिशत की वृद्धि है। सिंधिया ने कहा, " इसलिए, 2023-2024 से 2024-25 की तुलना में वृद्धि दर मात्र तीन प्रतिशत है। इसे हम वित्त वर्ष 2025-26 में 10 गुना कर 30 प्रतिशत करने का इरादा रखते हैं।" मंत्री ने कहा कि विभाग वर्तमान में सरकार के लिए एक व्यय केंद्र है और अगले चार से पांच वर्ष में लाभ केंद्र बनने का लक्ष्य रखता है।

पश्चिम रेलवे द्वारा विभिन्न गंतव्यों के बीच विशेष ट्रेनों का संचालन

ट्रेन नंबर	प्रारंभिक स्टेशन और गंतव्य	सेवा की तारीखें	प्रस्थान	आगमन
09005	बांद्रा टर्मिनस - भिवानी (सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल)	28.01.2026 to 25.02.2026	11:00 hrs (बुधवार)	13:00 hrs (अगले दिन)
09006	भिवानी- बांद्रा टर्मिनस (सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल)	29.01.2026 to 26.02.2026	14:35 hrs (गुरूवार)	16:10 hrs (अगले दिन)

ठहरावः बोरीवली, पालघर, वापी, सूरत, वडोदरा, रतलाम, मंदसौर, नीमच, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बिजयनगर, नसीराबाद, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, दौसा, अलवर, रेवाड़ी, कोसली एवं चरखी दादरी स्टेशन पर दोनों दिशाओं में ठहराव होगा।

संरचनाः एसी द्वितीय श्रेणी, एसी तृतीय श्रेणी, शयनयान श्रेणी तथा सामान्य द्वितीय श्रेणी के कोच।

09035	बांद्रा टर्मिनस - उधना (सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल)	30.01.2026 to 28.02.2026	09:00 hrs (शुक्र और शनि)	15:05 hrs (उसी दिन)
09036	उधना - बांद्रा टर्मिनस (सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल)	29.01.2026 to 27.02.2026	15:45 hrs (गुरू और शुक्र)	21:35 hrs (उसी दिन)

ठहरावः अंधेरी, बोरीवली, वसई रोड, विरार, वैतरणा, सफाले, केलवे रोड, पालघर, बोईसर, वंगांव, दहानू रोड, घोलवड़, बोर्डी रोड, उमरगाम रोड, संजान, भिलाड, करंबेली, वापी, वलसाड, बिलीमोरा तथा नवसारी स्टेशन पर दोनों दिशाओं में ठहराव होगा।
ट्रेन संख्या 09035 का अतिरिक्त ठहराव भायंदर पर होगा तथा ट्रेन संख्या 09036 का अतिरिक्त ठहराव अतुल, पारडी और उडवाड़ा पर होगा।
संरचनाः शयनयान श्रेणी एवं सामान्य द्वितीय श्रेणी के कोच।

09561	बांद्रा टर्मिनस - ओखा (साप्ताहिक विशेष)	28.01.2026 to 25.02.2026	05:50 hrs (बुधवार)	22:50 hrs (उसी दिन)
09562	ओखा - बांद्रा टर्मिनस (साप्ताहिक विशेष)	27.01.2026 to 24.02.2026	10:20 hrs (मंगलवार)	04:20 hrs (अगले दिन)

ठहरावः बोरीवली, सूरत, भरूच, वडोदरा, अहमदाबाद, विरमगाम, सुरेन्द्रनगर, राजकोट, हापा, जामनगर, खंभालिया तथा द्वारका स्टेशन पर दोनों दिशाओं में ठहराव होगा।

संरचनाः एसी द्वितीय श्रेणी, एसी तृतीय श्रेणी, एसी तृतीय श्रेणी इकोनॉमी, शयनयान श्रेणी तथा सामान्य द्वितीय श्रेणी के कोच।

समय-सारिणी, ठहराव (हॉल्ट) तथा संरचना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाएँ।

ट्रेन संख्या 09005, 09035, 09036, 09561 और 09562 के लिए बुकिंग सभी पीआरएस काउंटरों तथा आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू है। उपरोक्त ट्रेनें विशेष किराये पर विशेष ट्रेन के रूप में चलाई जाएंगी।

पश्चिम रेलवे
wr.indianrailways.gov.in
Like us & Follow us on:
facebook.com/WesternRly
X.com/WesternRly
Instagram.com/WesternRly
https://www.youtube.com/@WesternRly
https://bit.ly/WesternRailwayOfficial

कृपया सभी रिज़र्व टिकटों के लिए ओरिजिनल आईडी प्रूफ साथ रखें।

रानी कपूर ने बहू प्रिया कपूर पर लगाया 30, 000 करोड़ की संपत्ति हड़पने का आरोप, दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका

मुंबई। ऑटो-पार्ट्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी सोना ग्रुप के उत्तराधिकार को लेकर छिड़ी कानूनी जंग अब एक नए और गंभीर मोड़ पर पहुँच गई है। दिवंगत उद्योगपति डॉ. सुरिंदर कपूर की 80 वर्षीय विधवा रानी कपूर ने अपनी बहू प्रिया कपूर के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। रानी कपूर ने आरोप लगाया है कि प्रिया ने उनके बेटे संजय कपूर की मौत के बाद धोखाधड़ी से पूरी पारिवारिक संपत्ति और कंपनियों पर नियंत्रण हासिल करने की साजिश रची।

अपने मुकदमे में, 80 वर्षीय रानी कपूर ने कहा है कि ट्रस्ट धोखाधड़ी से बनाया गया था और इसका इस्तेमाल उन्हें उनकी पूरी संपत्ति से वंचित करने के लिए किया गया, जिसमें सोना ग्रुप कंपनियों पर नियंत्रण भी शामिल है। उन्होंने कहा कि संजय कपूर की विधवा प्रिया कपूर इस साजिश की 'मुख्य मास्टरमाइंड' हैं। दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की 80 वर्षीय मां, रानी कपूर ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक नया मुकदमा दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि प्रिया कपूर ने उन्हें धोखा देने के लिए हेरफेर किया। यह प्रिया, जो संजय की तीसरी पत्नी थीं, और अभिनेता करिश्मा कपूर के बच्चों के बीच उनके पति की 30, 000 करोड़ रुपये की संपत्ति को लेकर चल रही विरासत की लड़ाई में नवीनतम घटनाक्रम है। नई याचिका रानी कपूर फैमिली ट्रस्ट की वैधता को चुनौती देती है। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रस्ट धोखाधड़ी से उनके नाम पर बनाया गया था, लेकिन इसका इस्तेमाल संपत्तियों का नियंत्रण बदलने के लिए किया गया। उन्होंने प्रिया पर इस साजिश की 'मुख्य मास्टरमाइंड' होने का आरोप लगाया।

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

ई-टेंडर सूचना

विषयः नगरपालिका पावर लॉन्ड्री में स्टीम से चलने वाले तीन रोलर आयरनर की मरम्मत और ओवरहॉलिंग का काम।

निविदा दस्तावेज़ आईडी क्रमांक	बोली क्रमांक_2026_MCGM_1270634_1
निविदा जारी करने एवं बिक्री की तिथि	21.01.2026 से 16:00 बजे
निविदा बिक्री की अंतिम तिथि एवं समय	28.01.2026 से 16:00 बजे
क) नाम	श्री. एन. टी. जाधव
ख) मोबाइल क्रमांक	9769005647
एमसीजीएम वेबसाइट	https://portal.mcgm.gov.in/ https://mahatenders.gov.in
ई-मेल पता	aempl.me@mcgm.gov.in

पीआरओ/2740/विज्ञा./2025-26

ई.ई.मैकेनिकल (दक्षिण)

भोजन से पूर्व एवं शौच के बाद साबुन से हाथ स्वच्छ धोएं।

कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार को सुनाई खरी-खरी

मुसलमानों से कागज मांगते-मांगते शंकराचार्य से कागज मांगने लगे भाजपाई

रायपुर **(एजेंसी)**। प्रयागराज माघ मेले में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की पालकी रोके जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस इसे सनातन का विरोध बताते हुए भाजपा को खरी खरी सुना रही है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने राजीव भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सरकार और भाजपा को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने मनरेगा और जमीनों की गाइडलाइन की दरों को लेकर भी सरकार को घेरा।

दीपक बैज ने कहा कि प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को शाही स्नान से रोके जाने और उनके साथ हुए दुर्व्यवहार की हम कड़ी आलोचना करते है। खुद को हिंदुओं का मसीहा बताने वाली भाजपा सरकार हिंदु संतों का अपमान कर रही है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पिछले 40 वर्षों से नियमित रूप से शाही स्नान करते आ रहे हैं और यह पहली बार है जब उन्हें इस अखंड धार्मिक परंपरा से रोका गया है। उन्होंने कहा कि मौनी अमावस्या का शाही स्नान एक अखंड परंपरा है, भाजपा सरकार ने शंकराचार्य जी को स्नान से रोक कर सनातन परंपरा का अपमान किया है।भाजपा भगवान शंकराचार्य की सत्ता को चुनौती देने का दुस्साहस कर रही है। किसी भी राजनैतिक दल सरकार मुख्यमंत्री या प्रशासन को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि कौन शंकराचार्य है।

यूपी की भाजपा सरकार द्वारा शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगना समूचे हिन्दू धर्म का अपमान है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अविमुक्तेश्वरानंद के सामने सिर झुकाया था, तब वह शंकराचार्य थे? जब तक उन्होंने गोहत्या पर सरकार से सवाल नहीं उठाया, तब तक वह शंकराचार्य थे? जब तक उन्होंने मंदिर के अधूरे प्राण प्रतिष्ठा का विरोध नहीं किया, तब तक वह शंकराचार्य थे? लेकिन अब वह शंकराचार्य नहीं रहे क्योंकि उन्होंने राजा के सामने सिर नहीं झुकाया। इसीलिए आज योगी उनसे दस्तावेज मांग रहे हैं? उन्होंने तीखा हमला करते हुए कहा कि बीजेपी के लोग मुसलमानों से कागज दिखाने को कहते थे। अब स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि वे एक शंकराचार्य से कागज़ मांग रहे हैं।

बेंगलुरु हवाई अड्डे पर दक्षिण कोरिया की महिला का यौन उत्पीड़न, कर्मचारी गिरफ्तार

बेंगलुरु **(एजेंसी)**। कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के दौरान दक्षिण कोरिया की एक महिला का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किये जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि इस मामले में एक निजी एयरलाइन के संविदा कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान मोहम्मद अफान अहमद (25) के रूप में हुई है। यह घटना 19 जनवरी को टर्मिनल-2 में उस समय हुई, जब महिला दक्षिण कोरिया जाने के लिए आव्रजन प्रक्रिया पूरी कर रही थी। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने महिला के बैग से बीप की आवाज आने का दावा करते हुए नियमित जांच के बहाने उसे पुरुषों के शौचालय के पास एक स्थान पर ले गया जहां अन्य लोग नहीं थे। आरोप है कि तलाशी के नाम पर उसने महिला को कई बार अनुचित तरीके से स्पर्श किया और गले लगाया। शिकायत में कहा गया है कि महिला द्वारा विरोध करने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। महिला ने तुरंत हवाई अड्डा के सुरक्षा कर्मियों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद आरोपी को हिरासत में लिया गया और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है।

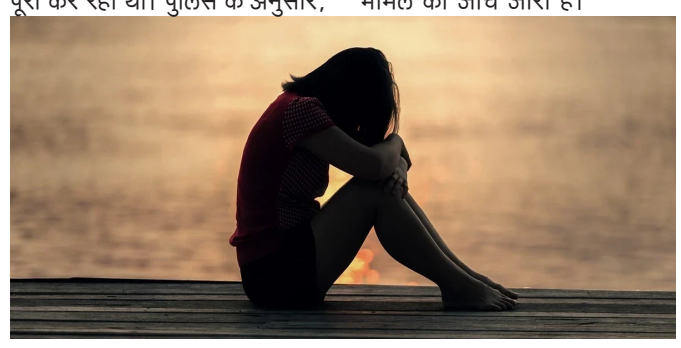

इंडिगो का लाभ तीसरी तिमाही में 78 प्रतिशत घटकर 549.1 करोड़ रुपये पर

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। विमानन कंपनी इंडिगो का लाभ चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 78 प्रतिशत घटकर 549.1 करोड़ रुपये रह गया। कंपनी की पिछले महीने व्यापक स्तर पर उड़ानें रद्द हुईं थीं।

कंपनी ने बृहस्पतिवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन को पिछले वर्ष की इसी तिमाही में 2, 448.8 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था।

इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन की कुल आय चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में बढ़कर 24, 540.6 करोड़ रुपये हो गई जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही में 22, 992.8 करोड़ रुपये थी।

इंडिगो को दिसंबर महीने की शुरुआत में व्यापक स्तर पर परिचालन व्यवधानों का सामना करना पड़ा था। इसके बाद नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयरलाइन के शीतकालीन उड़ान कार्यक्रम को 10 फरवरी तक 10 प्रतिशत तक घटा दिया था।

सीएम देवेन्द्र फडणवीस की दावोस यात्रा को राउत ने बताया पिकनिक, अमृता फडणवीस ने किया पलटवार

मुम्बई **(एजेंसी)**। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के दावोस दौरे को लेकर राज्य की राजनीति में जबरदस्त घमासान मच गया है। दरअसल, शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के दावोस दौरे पर तीखा हमला बोलते हुए इसे पिकनिक करार दिया है। संजय राउत ने सवाल उठाया कि आखिर भारतीय राज्यों के मुख्यमंत्री हर साल दावोस जाकर क्या साबित करना चाहते हैं? संजय राउत ने कहा कि देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री दावोस में इकट्ठा होकर आपस में बातचीत करते हैं और भारतीय कंपनियां वहीं समझौते करती हैं। उन्होंने कहा कि यह सारा तमाशा जनता के पैसे पर होता है और जो करार दावोस में किए जा रहे हैं वे मुंबई में बैठकर भी हो सकते थे। संजय राउत ने साफ शब्दों में कहा कि भारतीय नजरिए से दावोस सम्मेलन हास्यास्पद है।

उन्होंने यह भी मांग की कि मुख्यमंत्री देश और राज्य को बताएं कि दावोस यात्रा पर कितना खर्च किया गया। हालांकि राउत ने यह भी जोड़ा कि अगर निवेश और रोजगार के जो आंकड़े सरकार बता रही है वे सही हैं तो उनका स्वागत किया जाना चाहिए।

वहीं संजय राउत के हमले का जवाब मुख्यमंत्री की पत्नी अमृता फडणवीस ने दिया और उनके बयान को पूरी तरह निराधार बताया। उन्होंने कहा कि पिकनिक पर जाने वाला व्यक्ति सुबह छह बजे से रात ग्यारह बजे तक लगातार बैठकें और सम्मेलन नहीं करता। अमृता फडणवीस ने कहा कि दावोस एक वैश्विक मंच है जहां दुनिया भर के प्रतिनिधि मिलते हैं और निवेश के नए रास्ते खुलते हैं। उन्होंने कहा कि वहां जाना हर राज्य प्रमुख की जिम्मेदारी है।

हम आपको यह भी बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने दावोस से बड़ी उपलब्धियों का दावा किया है। महाराष्ट्र सरकार ने विश्व आर्थिक मंच के पहले ही दिन चौदह लाख पचास हजार करोड़ रुपये के 19 समझौतों पर हस्ताक्षर कर दिये थे। ये निवेश हरित ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण, इस्पात निर्माण, आईटी, डाटा सेंटर, इलेक्ट्रिक वाहन, जहाज निर्माण और डिजिटल ढांचे जैसे क्षेत्रों में होंगे। राज्य सरकार का दावा है कि इससे राज्य में पंद्रह लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

पर्यावरण कानून का उल्लंघन : ग्रीन ट्रिब्यूनल ने टेक्नीशियन की मौत पर नोएडा अथॉरिटी को नोटिस जारी किया

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। नोएडा के सेक्टर 150 में जलभराव वाले गड्ढे में गिरकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की दुखद मृत्यु के मामले में अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने कड़ा रुख अपनाया है। गुरुवार को इस घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए ट्रिब्यूनल ने नोएडा प्राधिकरण को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। ट्रिब्यूनल का यह कदम 20 जनवरी, 2026 को प्रकाशित एक न्यूज़ रिपोर्ट के बाद आया, जिसका शीर्षक था 'नोएडा के सीईओ हटाए गए, सीएम ने टेक्नीशियन के डूबने के मामले में एघ्रछ जांच के आदेश दिए'। नोटिस में, एनजीटी ने कहा कि रिपोर्ट पर्यावरण नियमों के पालन और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के संबंध में महत्वपूर्ण सवाल उठाती है।

आदेश में, ट्रिब्यूनल ने नोएडा अथॉरिटी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यूपी के सिंचाई विभाग, यूपी सरकार के पर्यावरण प्रधान सचिव और गौतम बुद्ध नगर के जिला मजिस्ट्रेट को प्रतिवादी बनाया है।

इन सभी संगठनों को अगली सुनवाई से कम से कम एक सप्ताह पहले हलफनामे के साथ अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है, जो 10 अप्रैल, 2026 को होनी है। एनजीटी ने जोर दिया कि यह मामला पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के संभावित उल्लंघन का संकेत देता है और कहा कि न्यूज़ रिपोर्ट पर्यावरण नियमों के प्रवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे उठाती है।

गुरुवार को अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले दिन में, लोटस ग्रीन्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और एमजेड विज़टाउन प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड के पांच बिल्डरों के खिलाफ सेक्टर 150 में एक बड़े पानी से भरे गड्ढे के संबंध में पर्यावरण और प्रदूषण कानूनों के कथित उल्लंघन के लिए एक और प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसके कारण एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो गई थी। यह प्राथमिकी ऐसे समय में दर्ज की गई है जब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गुरुवार को तीसरे दिन भी मामले की जांच जारी रखे हुए है।

घटनाक्रम से परिचित अधिकारियों ने बताया कि एसआईटी ने नोएडा अथॉरिटी के विभिन्न विभागों, जिसमें सिविल, प्रोजेक्ट्स और ट्रैफिक सेल शामिल हैं, से सेक्टर 150 में किए गए कार्यों के बारे में विवरण मांगा है, खासकर उस जगह के आसपास जहां सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हुई थी।

बांग्लादेश के रोहिंग्या शिविर में लगी भीषण आग सैकड़ों झोपड़ियां राख, हजारों ज्यादा शरणार्थी बेघर

ढाका **(एजेंसी)**। बांग्लादेश के कॉक्स बाज़ार जिले में स्थित रोहिंग्या शरणार्थी शिविर में मंगलवार तड़के लगी भीषण आग ने भारी तबाही मचा दी। कैंप-16 में आग से 335 अस्थायी झोपड़ियाँ पूरी तरह जल गईं और 72 अन्य को नुकसान पहुंचा। इस हादसे में 2, 000 से अधिक रोहिंग्या शरणार्थी बेघर हो गए। दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने में करीब तीन घंटे लगे। राहत की बात यह रही कि कोई मौत नहीं हुई, हालांकि कुछ लोगों को मामूली चोटें आईं। लेकिन हजारों लोगों ने अपने घरों के साथ-साथ जरूरी सामान, पहचान पत्र और अहम दस्तावेज़ भी खो दिए। संयुक्त राष्ट्र की इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन फॉर माइग्रेशन (आईओएम) ने कहा कि यह आग उन परिवारों के लिए नई मानवीय आपदा बन गई है, जो पहले ही कठिन हालात में जी रहे थे।

आईओएम के बांग्लादेश प्रमुख लांस बोनो ने कहा, 'भीड़भाड़ वाले शिविरों में आग लगने से असर सिर्फ ढांचे तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सुरक्षा और बुनियादी सेवाओं तक पहुंच भी खतरे में पड़ जाती है।' नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल (एनआरसी) के अनुसार, आग से पानी और स्वच्छता केंद्र, 11 लर्निंग सेंटर, रास्ते और अन्य बुनियादी ढांचे भी क्षतिग्रस्त हुए। फिलहाल आईओएम, एनआरसी और अन्य एजेंसियां कंबल, मच्छरदानी, खाना पकाने का सामान, हाइजीन किट और सोलर लाइट जैसी आपात सहायता उपलब्ध करा रही हैं। गौरतलब है कि 2017 में म्यांमार की सेना की कार्रवाई के बाद 7 लाख से अधिक रोहिंग्या बांग्लादेश आए थे। इसके बाद से म्यांमार के राखाइन प्रांत में जारी संघर्ष के चलते हजारों और शरणार्थी कॉक्स बाज़ार पहुंचते रहे हैं।राहत एजेंसियों ने बताया कि शिविरों में बने बांस और प्लास्टिक से ढके अस्थायी घर, जो सिर्फ 6-12 महीने के लिए थे, आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं और आग के लिए बेहद संवेदनशील हैं।

एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से 2025 के बीच 2, 425 आग की घटनाएं हो चुकी हैं, जिनसे 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। एनआरसी ने कहा कि 50, 000 अर्ध-पक्के शेल्टर बनाने की योजना थी, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मदद में भारी कटौती के कारण यह रोकनी पड़ी। खासतौर पर अमेरिका और यूरोपीय देशों की सहायता में कटौती से फंडिंग संकट गहरा गया है। 2025 में रोहिंग्या राहत के लिए जरूरी धन का सिर्फ आधा हिस्सा मिला, जिससे 466.6 मिलियन डॉलर का घाटा रहा। राहत संगठनों ने चेतावनी दी कि अगर तुरंत फंड नहीं बढ़ाया गया, तो ऐसी आग की घटनाएं बार-बार होती रहेंगी और शरणार्थियों को बार-बार शून्य से जीवन शुरू करना पड़ेगा।

डब्ल्यूईएफ में ट्रंप पर गरजे कैलिफोर्निया के गवर्नर, बोले-'अमेरिका पर 'डॉन' कर रहा राज, कांग्रेस बनी तमाशबीन'

वाशिंगटन **(एजेंसी)**। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूज़म ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) 2026 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा हमला बोला। सेमाफ़ोर के बेन स्मिथ के साथ इंटरव्यू में न्यूज़म ने कहा कि अमेरिका आज 'रूल ऑफ डॉन' के तहत जी रहा है, जहाँ लोकतंत्र की बुनियादी संस्थाएँ कमजोर पड़ गई हैं। न्यूज़म ने कहा, 'समानांतर सत्ता की शाखाएं, कानून का राज और जन-सत्ता क्या आज का अमेरिका वही है?' उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस निष्क्रिय बनी हुई है और कानून का शासन कमजोर हो रहा है। डब्ल्यूईएफ के चौथे दिन हुई चर्चा में न्यूज़म ने अमेरिकी विश्वविद्यालयों, कानून फर्मों और कॉरपोरेट नेतृत्व पर भी निशाना साधा। उन्होंने प्रतीकात्मक तौर पर लाल नी-पैड्स दिखाते हुए कहा कि जैसे कुछ संस्थान प्रशासन के आगे झुक रहे हैं, वैसे ही ये पैड्स बिक रहे हैं हालाँकि उन्होंने किसी सीईओ का नाम नहीं लिया। दावोस के नियमित प्रतिभागी न्यूज़म को उनके तीखे और बहसात्मक भाषणों पर तालियाँ भी मिलीं। उन्होंने बताया कि दावोस आने का एक मकसद पूँजीवाद के भविष्य पर ट्रंप के दृष्टिकोण का विरोध करना है। इस बीच, ट्रंप ने अपने दावोस भाषण में न्यूज़म का ज़िक्र करते हुए उन्हें 'गुड गाइ' कहा और पुराने अच्छे संबंधों की बात की।

दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर जांच के दौरान मिला नरकंकाल, पुलिस ने फोरेंसिक जांच के लिए भेजा

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब सुरक्षाकर्मियों ने नियमित सामान जांच के दौरान एक मानव कंकाल जैसा कुछ पाया, जिससे तत्काल अलर्ट जारी हुआ और हवाई अड्डे को खाली कराया गया। हवाई अड्डे की सुरक्षा और दिल्ली पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने और जांच शुरू करने के लिए तुरंत हस्तक्षेप किया। यात्रियों की बढ़ती चिंता के बीच घटी इस घटना को जल्द ही एक मेडिकल छात्र से संबंधित हानिरहित शैक्षिक उपकरण बताकर खारिज कर दिया गया। सामान्य सुरक्षा जांच के दौरान, टी3 पर एक यात्री के बैग में स्कैनर ने एक संदिग्ध वस्तु को चिह्नित किया, जिससे पता चला कि उसमें मानव हड्डियों से मिलते-जुलते कंकाल के अवशेष थे। पास में मौजूद यात्री तस्करी या इससे भी बदतर किसी घटना के डर से घबरा गए, जिससे अस्थायी रूप से अफरा-तफरी मच गई और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। सुरक्षा टीमों ने इलाके को घेर लिया और किसी भी आपराधिक संलिप्तता का पता लगाने के लिए गहन जांच हेतु दिल्ली पुलिस को बुलाया। इस घटना ने दिल्ली के सबसे व्यस्त टर्मिनल जैसे उच्च यातायात वाले केंद्रों में नियमित सतर्कता और जनता के भय के बीच की बेहद नाजुक स्थिति को उजागर किया।

पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में पता चला कि कंकाल एक वास्तविक प्रदर्शन मॉडल था, जिसका उपयोग आमतौर पर मेडिकल छात्र शरीर रचना विज्ञान के प्रशिक्षण के लिए करते हैं। यह कंकाल एक वैध छात्र यात्री के सामान में मिला था। जांच में किसी प्रकार की गड़बड़ी के संकेत नहीं मिले, जिससे अवैध गतिविधि की शुरुआती आशंकाएं दूर हो गईं। सभी संदेहों को दूर करने के लिए, अधिकारियों ने वस्तु को फोरेंसिक विश्लेषण के लिए भेज दिया।

दावोस से कनाडा की अमेरिका को खुली चुनौती

प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की स्पीच बनी ट्रंप पर सबसे बड़ा तमाचा, वायरल हो रहा खास वाक्य

ओटावा **(एजेंसी)**। दावोस में इस बार जो माहौल दिखा, वह अभूतपूर्व था। विश्व आर्थिक मंच के मंच से कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिका की दशकों पुरानी वैश्विक दादागीरी पर सीधा प्रहार किया। डोनाल्ड ट्रंप के दावोस पहुंचने से ठीक पहले दिया गया यह भाषण अब तक का उनका सबसे साहसिक और तीखा बयान माना जा रहा है। कार्नी ने साफ शब्दों में कहा कि जिस 'नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था' ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया को दिशा दी, वह अब टूट चुकी है। अब नियम नहीं, बल्कि ताकत की राजनीति चल रही है। उन्होंने चेताया कि बीते दौर की यादों में जीना अब कोई रणनीति नहीं रह गई है। कार्नी ने अपनी स्पीच में भारत और चीन का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यूरोप अब अपने आर्थिक और रणनीतिक भविष्य के लिए इन देशों की ओर देख रहा है। यूरोपीय संघ और भारत के बीच संभावित 'मदर ऑफ ऑल डील्स' इसी बदले हुए वैश्विक संतुलन का संकेत है। कार्नी ने दो टूक कहा कि दुनिया अब अमेरिका के इशारों पर नहीं चलेगी। उन्होंने ट्रंप की उस टिप्पणी पर भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें कनाडा को अमेरिका का '51वां राज्य' कहा गया था। कार्नी बोले-'कनाडा किसी की जागीर नहीं है। हमारी संप्रभुता पर कोई सौदा नहीं होगा।' भाषण का सबसे चर्चित वाक्य यही रहा। कार्नी ने कहा कि मध्यम ताकत वाले देशों के लिए अब नया नियम है 'अगर आप फैसले की मेज पर नहीं बैठे, तो आप मेनू में शामिल कर लिए जाएंगे।' उन्होंने छोटे और मध्यम देशों से एकजुट होने की अपील की। डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड पर दावों को लेकर कार्नी ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि कनाडा, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है और ग्रीनलैंड का भविष्य तय करने का अधिकार केवल वहां के नागरिकों को है।

उड़ा दिया जाएगा, दावोस में पीस बोर्ड पर साइन करते हुए हमास को ट्रंप की लास्ट वार्निंग

दावोस **(एजेंसी)**। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को हमास को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह हथियार छोड़ने पर सहमत नहीं होता है तो उसे उड़ा दिया जाएगा। उन्होंने दावोस में विश्व आर्थिक मंच के दौरान गाजा पर केंद्रित अपने 'शांति बोर्ड' के हस्ताक्षर समारोह की अध्यक्षता की। कई विश्व नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में आयोजित इस उच्चस्तरीय समारोह में ट्रंप ने कहा कि हमास द्वारा निरस्त्रीकरण पर कोई समझौता नहीं होगा और इसे अपने नवस्थापित शांति ढांचे की पहली परीक्षा बताया। ट्रंप ने दावोस में पहले दिए गए अपने बयान को दोहराते हुए कहा कि अगर हमास हथियार छोड़ने पर सहमत नहीं होता है, तो उन्हें उड़ा दिया जाएगा। वाशिंगटन को अगले दो या तीन दिनों में, निश्चित रूप से अगले तीन हफ्तों में' पता चल जाएगा कि क्या समूह अनुपालन करने का इरादा रखता है।

इस कार्यक्रम में बोर्ड ऑफ पीस चार्टर का औपचारिक शुभारंभ हुआ, जो एक ऐसी पहल है जिसे ट्रंप ने गाजा में युद्धविराम प्रवर्तन, पुनर्निर्माण और सुरक्षा समन्वय की देखरेख के लिए एक तंत्र के रूप में पेश किया है, साथ ही इसके दायरे को क्षेत्र से परे संघर्षों से निपटने के लिए विस्तारित किया है। हस्ताक्षर करने के लिए बहरीन और मोरक्को के नेता भी ट्रंप के साथ मौजूद थे, जबकि अन्य नेता भी दो-दो करके हस्ताक्षर करने के लिए आगे आए। अज़रबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव भी समारोह में उपस्थित थे। ट्रंप ने कहा कि हम जो कर रहे हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं वास्तव में यहाँ आकर यह करना चाहता था, और मुझे इससे बेहतर जगह कोई और नहीं सूझी। दस्तावेजों के ढेर पर हस्ताक्षर करने के बाद, ट्रंप ने मुस्कुराते हुए उन्हें कैमरों के सामने लहराया और फिर अन्य नेताओं को हस्ताक्षर करने के लिए आमंत्रित किया।

Facebook: https://www.facebook.com/profile.phpid=100063787346044 **Twitter:** https://twitter.com/mantrabharatt=8tJONQ7H-h6EKqqap2tVMw&s=08 **Mobile No:** 7007837917

मंत्र भारत : R.N.I. MAHHIN/ 2016/65841 स्वात्वाधिकारी राकेश शर्मा के लिए राकेश शर्मा द्वारा AIS Printing solution प्लॉट नं0-A- 544 TTC इंडस्ट्रियल एरिया एमआईडीसी माहपे-नवी मुंबई, थाने 400709 से मुद्रित एवं शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012प्रकाशित एवं सम्पादित। कार्यालय : शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012 । फोन : 022-24706563 । कार्यकारी सम्पादक- योगेन्द्र चौधरी
E-Mail : editormantrabharat@gmail.com mantrabharatmumbai@gmail.com । सम्पादक : विनोद आर शर्मा, मोबाइल : 7007837917 । समूह सम्पादक : डॉ दयानन्द तिवारी। वैधानिक सूचना : मंत्र भारत से संबंधित समस्त विवाद निपटारे के लिए मंत्र प्रधान कार्यालय क्षेत्र प्रयागराज/ इलाहाबाद न्यायालय ही होगा। प्रधान कार्यालयः 80ए मेंहदौरी, तेलियरगंज, प्रयागराज-211004 (नोटः कानूनी पत्र व्यवहार का पता प्रधान कार्यालय ही होगा।)